▸▸ वर्ष : 34 ▸▸ अंक : 376 ▸▸ मुंबई, बुधवार, 25 मार्च 2026 ▸▸ RNI: MAHHIN/49994/91 ▸▸ मूल्य : 3 रुपए ▸▸ epaper.dobajedopahar.com ▸▸ संपादक : अरुण लाल ▸▸ संरक्षक : एन. के. पुरोहित

DBD दो बजे दोपहर

पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पांसिबिलिटी है

SIT का गठन और सोशल मीडिया पर कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल (SIT) बना दिया गया है। पीड़ितों के जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, उन्हें साइबर विभाग हटाने की प्रक्रिया कर रहा है। साथ ही, जिन मीडिया संस्थानों ने पीड़ितों की पहचान उजागर की, उन्हें कड़े नोटिस जारी किए गए हैं। NATGRID के माध्यम से आरोपी के बैंक खातों और कॉल रिकॉर्ड्स की गहन जांच की जा रही है।

पीड़ित महिलाओं का सामने आना शुरू

मुख्यमंत्री ने बताया कि शुरुआत में कोई भी पीड़िता सामने नहीं आ रही थी, लेकिन पुलिस के भरोसे के बाद अब तक 6 महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई है। अन्य संभावित पीड़ितों की तलाश जारी है। यह मामला केवल ब्लैकमेलिंग या अश्लील सामग्री तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े संगठित आपराधिक नेटवर्क की ओर संकेत करता है। कॉल रिकॉर्ड, बैंक खातों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जांच NATGRID के माध्यम से की जा रही है।

40 करोड़ की संपत्ति का खुलासा

मुख्यमंत्री ने सदन में खोली अशोक खरात की पोल

भोंदू बाबा का कच्चा चिट्ठा

- देवी अवतार बनकर महिलाओं का शोषण, अब तक 8 केस दर्ज
- खरात के काले कारनामों में एआई का इस्तेमाल
- देश छोड़कर विदेश भागने की फिराक में था भोंदू बाबा

अमित बृज | मुंबई

नासिक के भोंदू बाबा अशोक खरात के पाखंड और अपराधों का कच्चा चिट्ठा मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में पेश किया। यह मामला केवल अंधविश्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लैकमेलिंग, यौन शोषण और 40 करोड़ रुपये से अधिक की काली कमाई का एक खतरनाक कॉकटेल सामने आया है।

अश्लील वीडियो और 5 करोड़ की रंगदारी से शुरू हुआ मामला

विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी और 5 करोड़ रुपये की रंगदारी से शुरू हुआ, जो अब एक बड़े आपराधिक नेटवर्क में बदलता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार, 29 दिसंबर 2025 को भद्रकाली पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत में दिनेश परब पर 'प्रिया' नाम की महिला को अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर 5 करोड़ रुपये मांगने का आरोप था। शुरुआती जांच में कुछ संदिग्ध नाम सामने आए, लेकिन साइबर जांच में सभी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले।

गिरफ्तारी और लुकआउट सर्कुलर

मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि अशोक खरात के देश छोड़कर भागने की प्रबल संभावना थी। इसे रोकने के लिए पुलिस ने 10 मार्च 2026 को ही लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया था। अंततः 17 मार्च 2026 को सरकारवाडा पुलिस स्टेशन में एक पीड़िता द्वारा बलात्कार और काले जादू (Black Magic Act) की शिकायत दर्ज कराने के बाद उसे रात 11:59 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।

ब्लैकमेलिंग का हाई-टेक नेटवर्क

अशोक खरात और उसके गिरोह ने महिलाओं को डराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का सहारा लिया। 18 फरवरी 2026 को शिरडी में दर्ज एक शिकायत के अनुसार, आरोपी ने एआई (AI) से तैयार की गई फर्जी अश्लील फोटो दिखाकर महिलाओं को बदनाम करने की धमकी दी। मोबाइल डेटा गायब होने के कारण शुरुआत में जांच कठिन थी, लेकिन साइबर विभाग ने अंततः सुराग ढूंढ निकाले।

नशीला पदार्थ पिलाकर सम्मोहन और यौन शोषण

मामले में सबसे घिनौना मोड़ तब आया जब पुलिस को 35 अश्लील वीडियो मिले, जिनमें 8 अलग-अलग महिलाओं का शोषण किया जा रहा था। आरोपी खुद को 'देवी शक्तियों' वाला बताता था और महिलाओं को उनके पति की मौत का डर दिखाकर, नशीला पदार्थ पिलाकर सम्मोहित करता था और फिर उनका शारीरिक व आर्थिक शोषण करता था।

40.87 करोड़ की अघोषित संपत्ति और हथियार

एसआईटी (SIT) जांच में पता चला कि इस 'ढोंगी बाबा' के पास नासिक, सिन्नर, शिरडी और पनवेल में फॉर्महाउस, फ्लैट और जमीन समेत 40.87 करोड़ रुपये की संपत्ति है। आरोपी के पास से 6.53 लाख रुपये नकद, एक रिवॉल्वर, 21 जिंदा कारतूस और दो लैपटॉप बरामद हुए हैं। यही नहीं, उसके आर्थिक लेन-देन के तार अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी जुड़े होने का शक है।

तारीख पर तारीख का खेल ख़त्म

धीरज सिंह | मुंबई

महाराष्ट्र के निवेशकों और छोटे बचतकर्ताओं के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा में एक ऐतिहासिक घोषणा की है। राज्य सरकार ने MPID एक्ट में बड़े संशोधनों का प्रस्ताव रखा है, जिससे अब धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों की संपत्तियां कुर्क करना और निवेशकों का पैसा लौटाना एक्सप्रेस रफ्तार से होगा।

- निवेशकों का धन वसूलने के लिए MPID कानून में संशोधन
- कुर्क संपत्ति की नीलामी 6 महीने के भीतर होगी अनिवार्य

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का विधानसभा में ऐलान

180 दिन की डेडलाइन

प्रस्तावित संशोधन के तहत अब नामित अदालत के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह आवेदन के 180 दिन (6 महीने) के भीतर संपत्ति की कुर्की को अंतिम घोषित करे। पहले संपत्तियां सालों तक केवल कागजों पर कुर्क रहती थीं और कानूनी पेचीदगियों के कारण उनकी नीलामी नहीं हो पाती थी। अब इस समयसीमा से निवेशकों को अपनी डूबी हुई रकम जल्द मिलने की उम्मीद जगी है।

श्रीरामपुर घोटाले और बेनामी संपत्तियों पर फोकस

गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने श्रीरामपुर के करोड़ों रुपये के वित्तीय घोटालों का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि घोटालेबाजों ने अपने परिवार या सहयोगियों के नाम पर जो बेनामी संपत्तियां छिपाई हैं, उन्हें भी अब प्रभावी ढंग से ट्रैक कर कुर्क किया जाएगा। एक विशेष टीम श्रीरामपुर जाकर इन जमीनों का 2026 के मौजूदा बाजार मूल्य पर पुनर्मूल्यांकन करेगी ताकि पीड़ितों को अधिकतम राशि मिल सके।

वकीलों की देरी वाली चाल पर लगाम

अक्सर बचाव पक्ष के वकील बार-बार सुनवाई टालने की मांग करते हैं जिससे मामला सालों खिंचता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब केवल दो बार ही स्थगन की अनुमति होगी। अगर कोई जानबूझकर देरी करने की कोशिश करेगा, तो अदालत उस पर भारी जुर्माना भी लगा सकेगी। न्याय की प्रक्रिया अब किसी के इंतजार में नहीं रुकेगी।

मुकदमे के साथ-साथ नीलामी का रास्ता साफ

संशोधन का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा यह है कि अब आपराधिक मुकदमा जारी रहने के दौरान भी कुर्क की गई संपत्तियों की नीलामी की जा सकेगी। फैक्ट्री या जमीन की नीलामी से प्राप्त राशि को तुरंत पीड़ितों में बांटा जा सकेगा। अब निवेशकों को पैसा पाने के लिए केस के पूरी तरह खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

नाबालिगों के सोशल मीडिया उपयोग पर जल्द बनेगी नीति

- टास्क फोर्स की रिपोर्ट का इंतजार

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

राज्य में नाबालिग बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को लेकर सरकार जल्द ठोस नीति बनाने की तैयारी में है। विधानसभा में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आशिष शेलार ने बताया कि इसके लिए गठित टास्क फोर्स की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके आधार पर आगे कानून या दिशा-निर्देश तय किए जाएंगे।

पूरी तरह प्रतिबंध संभव नहीं

मंत्री ने स्पष्ट किया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया या मोबाइल उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि शिक्षा में इंटरनेट की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए सरकार संतुलित और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाएगी।

टास्क फोर्स कर रही व्यापक अध्ययन

भाजपा विधायक राजेश पवार द्वारा उठाए गए मुद्दे के जवाब में मंत्री शेलार ने कहा कि 2 फरवरी 2026 को गठित टास्क फोर्स बच्चों पर सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रभाव का अध्ययन कर रही है। इसमें मानसिक, शारीरिक और शैक्षणिक प्रभावों के साथ-साथ डिजिटल विज्ञापनों के असर और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय नियमों का भी विश्लेषण शामिल है।

रिपोर्ट के बाद लिए जाएंगे अहम फैसले

टास्क फोर्स को तीन महीने में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद उम्र सत्यापन (Age Verification), स्क्रीन टाइम सीमा, आईटी कानूनों में बदलाव और स्कूलों में डिजिटल सुरक्षा शिक्षा जैसे उपायों पर निर्णय लिया जाएगा। साथ ही छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू करने की योजना है।

ब्रीफ न्यूज़

आरटीई छात्रों से फीस वसूली पर सख्ती

मुंबई। राज्य में आरटीई (शिक्षा का अधिकार) के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों से किसी भी प्रकार की फीस या 'सामग्री' के नाम पर पैसे वसूलना पूरी तरह प्रतिबंधित है। विधानसभा में स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाजपा विधायक योगेश सागर के सवाल के जवाब में मंत्री भुसे ने बताया कि आरटीई कानून 2009 के तहत निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर वंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य है। इन छात्रों की फीस का भुगतान सरकार करती है, इसके बावजूद कुछ स्कूल अभिभावकों से अन्य नामों पर पैसे वसूल रहे हैं, जो पूरी तरह अवैध है। मंत्री ने बताया कि 1 जुलाई 2015 को ही सभी स्कूलों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे कि आरटीई छात्रों से कोई अतिरिक्त शुल्क न लिया जाए। यदि किसी स्कूल ने ऐसा किया है, तो उनसे वसूली गई राशि वापस कराई जाएगी और संबंधित स्कूलों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी।

आसिया अंद्राबी को आजीवन कारावास

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार (24 मार्च) को जम्मू-कश्मीर की अलगाववादी चरमपंथी नेता आसिया अंद्राबी को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने आतंकी संगठन का सदस्य होने, आतंकी साजिश रचने और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने से जुड़े मामलों में जनवरी में ही आसिया को दोषी ठहराया था और सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने इस सजा का एलान किया है। आसिया अंद्राबी, यह नाम आज शायद लोगों के दिमाग से कुछ हद तक मिट चुका है। लेकिन 1980 से 2000 के दशक तक यह नाम जम्मू-कश्मीर में दहशत का पर्याय था।

प्रदेश में बनेगी नई सहकारिता नीति

15 सदस्यीय समिति गठित

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

राज्य में सहकारिता क्षेत्र को अधिक मजबूत, पारदर्शी और गतिशील बनाने के लिए जल्द ही नई सर्वसमावेशीय सहकारिता नीति लागू की जाएगी। विधान परिषद में सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटील ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी मॉडल बनाना है। भाजपा विधायक प्रवीण दरेकर द्वारा उठाए गए मुद्दे

के जवाब में मंत्री पाटील ने कहा कि नई नीति का मसौदा तैयार करने के लिए 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति सहकारिता क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों और संभावनाओं का अध्ययन कर सुझाव देगी।

मुंबई में भी सहकारिता का बड़ा नेटवर्क

मंत्री ने कहा कि यह धारणा गलत है कि मुंबई जैसे महानगर का सहकारिता विभाग से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि मुंबई में ही करीब 1.25 लाख सहकारी संस्थाएं पंजीकृत हैं, जबकि पूरे राज्य में लगभग 2.33 लाख सहकारी संस्थाएं कार्यरत हैं। पाटील ने जानकारी दी कि राज्य में 128 सहकारी और 134 निजी चीनी कारखाने संचालित हैं, जो सहकारिता क्षेत्र की व्यापकता और महत्व को दर्शाते हैं। नई नीति से इस क्षेत्र को और गति मिलने की उम्मीद है।

अजित पवार मौत प्रकरण पर विधानसभा में घमासान

- सीबीआई जांच को लेकर गरमाई सियासत

दीपक पवार | मुंबई

विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम सप्ताह में पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़े मौत प्रकरण को लेकर जोरदार बहस देखने को मिली। राकांपा (अजित) विधायक रोहित पवार ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश के बावजूद केंद्र सरकार ने अब तक CBI जांच को मंजूरी नहीं दी है, जिसे उन्होंने संवेदनहीनता करार दिया।

विपक्ष ने उठाए सवाल

रोहित पवार ने कहा कि मामले में न्याय के लिए गंभीर प्रयास नहीं हो रहे हैं, इसलिए अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को भी अपने पति की मौत की CBI जांच के लिए केंद्र से गुहार लगानी पड़ रही है, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है।

सत्ता पक्ष का पलटवार

विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध जताया। भाजपा विधायक सुधीर मुनगंटीवार और अमित साटम ने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसे मामलों को उठाकर ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस मुद्दे को इस समय उठाने को अनुचित बताया।

सदन में हंगामा

इस मुद्दे को लेकर सदन में कुछ समय तक हंगामे की स्थिति बनी रही। विपक्ष जहां CBI जांच की मांग पर अड़ा रहा, वहीं सत्ता पक्ष ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। फिलहाल, इस मामले में केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार किया जा रहा है, जिस पर आगे की सियासत निर्भर करेगी।

टिकट कैंसिलेशन और बोर्डिंग नियमों में बदलाव, अप्रैल से लागू

टिकट कैंसिल करने में देरी पड़ेगी भारी

एजेंसी | नई दिल्ली

भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए टिकट कैंसिलेशन और बोर्डिंग प्वाइंट बदलने के नियमों में अहम बदलाव किए हैं। नए नियमों के लागू होने से यात्रियों को यात्रा से पहले अधिक लचीलापन मिलेगा और उनकी प्लानिंग आसान हो सकेगी। रेलवे इन बदलावों को 1 से 15 अप्रैल के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा।

72 घंटे पहले कैंसिल पर लगभग पूरा रिफंड

नए नियमों के तहत यदि यात्री अपनी कन्फर्म टिकट यात्रा से 72 घंटे पहले कैंसिल करता है, तो उसे लगभग पूरी राशि वापस मिल जाएगी। इस दौरान केवल एक तय फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज ही काटा जाएगा, जिससे समय रहते टिकट रद्द करने वालों को बड़ा फायदा होगा।

24 से 72 घंटे के बीच 25% कटौती

यदि टिकट यात्रा से 72 घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच कैंसिल की जाती है, तो रेलवे किराए का 25 प्रतिशत हिस्सा काटेगा और शेष राशि वापस कर देगा। इससे यात्रियों को आंशिक राहत मिलेगी, लेकिन देरी के साथ कटौती बढ़ेगी।

24 से 8 घंटे के बीच आधा किराया रिफंड

यात्रा से 24 घंटे से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर केवल 50 प्रतिशत किराया ही वापस मिलेगा। इस समयावधि में कैंसिलेशन करना यात्रियों के लिए महंगा साबित हो सकता है।

8 घंटे से कम समय पर कोई रिफंड नहीं

यदि ट्रेन छूटने में 8 घंटे से कम समय बचा है और यात्री टिकट कैंसिल करता है, तो किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं मिलेगा। रेलवे ने अंतिम समय में सीट खाली होने की स्थिति को रोकने के लिए यह सख्त नियम लागू किया है।

बोर्डिंग प्वाइंट बदलने में बड़ी राहत

रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए बोर्डिंग प्वाइंट बदलने के नियमों में ढील दी है। अब यात्री ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से सिर्फ 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। रेलवे मंत्रालय का कहना है कि यह सुविधा खासकर बड़े शहरों में काफी मददगार साबित होगी, जहां एक से ज्यादा रेलवे स्टेशन होते हैं। इससे यात्री अपनी सहूलियत के अनुसार नजदीकी स्टेशन से यात्रा शुरू कर पाएंगे।

पुराना टिकट कैंसिलेशन नियम

रेलवे के पुराने टिकट कैंसिलेशन नियमों में चार्ज क्लास और समय सीमा के हिसाब से तय होता था। पहले अगर कोई यात्री 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता था, तो एग्जीक्यूटिव क्लास पर 240 रुपये के साथ जीएसटी और एसी चेयर कार पर 180 रुपये के साथ जीएसटी काटे जाते थे। इसके बाद 48 से 12 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करने पर किराए का 25 प्रतिशत कटता था।

धर्मांतरण पर सुप्रीम फैसला

धर्म बदलने पर नहीं मिलेगी एससी-एसटी एक्ट की सुरक्षा

एजेंसी | मुंबई/नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2026 को अहम फैसला सुनाते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति (SC) के लाभ देने से इनकार किया गया था। कोर्ट ने साफ कहा कि जो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म का पालन नहीं करता, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। धर्म परिवर्तन करते ही उसका SC वर्गीकरण तुरंत समाप्त हो जाता है।

क्या था मामला?

यह मामला एक ईसाई पादरी से जुड़ा था, जिसने एससी-एसटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था का अस्तित्व नहीं है, इसलिए धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति SC का लाभ नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इसी तर्क को सही ठहराते हुए कहा कि धर्म बदलने के बाद एससी-एसटी एक्ट के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा भी लागू नहीं होगी।

पत्थर से कुचलकर डिलीवरी मैन की बेरहमी से हत्या

डीबीडी संवाददाता । उल्हासनगर

शहर में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के बीच एक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। उल्हासनगर कैंप-1 के शिवनेरी नगर में सोमवार शाम करीब 5 बजे एक युवक की पत्थर से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। मृतक की पहचान प्रवीण अशोक वर्मा (27) के रूप में हुई है, जो फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता था। शुरुआती जानकारी के अनुसार, अज्ञात हमलावर ने उसके सिर पर बड़ा पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। गौरतलब है कि हाल ही में एक सफाई कर्मचारी की 32 बार चाकू घोंपकर हत्या की घटना ने शहर को हिला दिया था। उसके बाद इस दूसरी हत्या ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना की सूचना मिलते ही उल्हासनगर पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी। पुलिस उपायुक्त (जोन-4) सचिन गोर और एसीपी अमोल कोली ने घटनास्थल का दौरा कर जांच की कमान संभाली।

दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

मृतक के भाई अभिषेक अशोक वर्मा की शिकायत पर पुलिस ने पप्या उर्फ शुभम अर्जुन पाटिल और एक अन्य आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पंचनामा कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया है। हत्या के पीछे का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। आशंका जताई जा रही है कि घटना के पीछे पुरानी रंजिश या अन्य आपराधिक वजह हो सकती है।

भिवंडी-निजामपुर मनपा का 1179 करोड़ का बजट पेश

डीबीडी संवाददाता । भिवंडी

विकास योजनाओं पर जोर, बुनियादी चुनौतियों पर उठे सवाल

भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका का वर्ष 2025-26 का संशोधित और 2026-27 का मूल बजट मंगलवार को पेश किया गया। मनपा आयुक्त अनमोल सागर (आईएएस) ने महापौर नारायण रतन चौधरी को करीब 1179.10 करोड़ रुपए का बजट सौंपा। बजट में 73.96 लाख रुपए की शिल्लक दर्शाई गई है, जबकि आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 241.51 करोड़ रुपए की प्रारंभिक शिल्लक का अनुमान रखा गया है। इस दौरान उपमहापौर तारीक अब्दुल बारी मोमीन समेत वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मनपा ने इस बजट को पानी आपूर्ति, सीवरेज, शिक्षा, परिवहन, अग्निशमन, महिला एवं बाल कल्याण, दिव्यांग कल्याण सहित कुल नौ प्रमुख विभागों में विभाजित किया है। साथ ही शासन के निर्देशानुसार सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए 326.40 लाख रुपए (5 प्रतिशत) का अलग प्रावधान किया गया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और जल परियोजनाओं को बढ़ावा

बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 59.42 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिनमें से 22 करोड़ रुपए अगले वर्ष के लिए आरक्षित हैं। अमृत 2.0 योजना के तहत 100 एमएलडी जलापूर्ति परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा सड़कों के चौड़ीकरण के तहत बिजली के खंभों के स्थानांतरण के लिए 2 करोड़ रुपए और अग्निशमन व तकनीकी विभाग में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए 3.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए बजट में कई अहम घोषणाएं की गई हैं। एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षा अभियान के तहत मनपा स्कूलों के लिए 1 करोड़ रुपए, पीएम ई-बस योजना के लिए 5 करोड़ रुपए तथा संपत्ति कर प्रणाली को मजबूत करने हेतु जीआईएस मैपिंग के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा और स्कूलों के उन्नयन पर ध्यान

मनपा स्कूलों के नवीनीकरण और मरम्मत के लिए 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके जरिए शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

पानी, ट्रैफिक और कचरा प्रबंधन बनी चुनौती

बजट में विकास योजनाओं के बावजूद शहर की प्रमुख समस्याओं को लेकर सवाल बरकरार हैं। जलापूर्ति परियोजनाओं के बावजूद पानी और सीवरेज संकट के समाधान के लिए स्पष्ट और दीर्घकालिक योजना का अभाव नजर आता है। वहीं बढ़ते ट्रैफिक जाम, अव्यवस्थित सड़कों और ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर भी ठोस रणनीति सामने नहीं आई है।

स्वास्थ्य सुविधाओं पर अपर्याप्त ध्यान

तेजी से बढ़ती आबादी के मुकाबले मनपा की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बजट में अपेक्षित प्रावधान नहीं दिखता, जिससे आने वाले समय में यह एक बड़ी चुनौती बन सकती है।

संतुलित बजट, लेकिन सुधार की गुंजाइश

विशेषज्ञों के अनुसार, यह बजट विकास और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। हालांकि भिवंडी जैसे तेजी से विस्तार कर रहे शहर के लिए बुनियादी सुविधाओं पर और अधिक निवेश की जरूरत महसूस की जा रही है।

अब क्रियान्वयन पर टिकी निगाहें

भिवंडी-निजामपुर मनपा का यह बजट शहर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब नागरिकों और विशेषज्ञों की नजर इस बात पर टिकी है कि घोषित योजनाओं का क्रियान्वयन कितनी प्रभावी तरीके से होता है और आम जनता को इसका कितना लाभ मिलता है।

कर वसूली में एमबीएमसी बनी धुरंधर

243 करोड़ का आंकड़ा पार

डीबीडी संवाददाता । भाईंदर

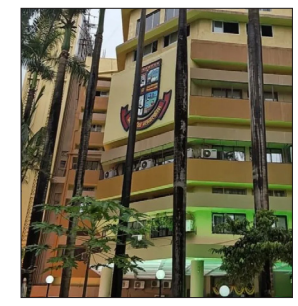

मीरा भाईंदर नगर निगम ने वित्त वर्ष 2025-26 के अंत में संपत्ति कर वसूली के मामले में रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की है। 23 मार्च 2026 की मध्यरात्रि तक निगम ने कुल 243.40 करोड़ से अधिक का कर वसूल कर अपनी वित्तीय स्थिति को बेहद मजबूत कर लिया है। आंकड़ों के अनुसार, मीरा भाईंदर के नागरिकों ने ऑनलाइन पेमेंट को ज्यादा प्राथमिकता दी है। लगभग 1.59 लाख संपत्ति मालिकों ने डिजिटल माध्यम से 128.91 करोड़ जमा किए। वहीं, 1.44 लाख लोगों ने चेक या नकद के जरिए ऑफलाइन 114.48 करोड़ का भुगतान किया। यह तकनीक और पारदर्शिता की बड़ी जीत है।

शहर के अलग-अलग वार्डों में वसूली का प्रदर्शन अलग रहा, लेकिन प्रभाग समिति 4 ने बाजी मार ली। इस अकेले प्रभाग से 89.72 करोड़ से अधिक का कर मिला है, जो पूरे शहर की कुल वसूली का एक बड़ा हिस्सा है। प्रभाग समिति 6 भी 62.99 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर रही।

निगम अब उन लोगों के प्रति कोई नरमी नहीं बरत रहा है जिन्होंने बार-बार नोटिस के बावजूद टैक्स नहीं भरा है। उपायुक्त डॉ. सचिन बांगर के नेतृत्व में पानी के कनेक्शन काटने और संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। प्रशासन का साफ संदेश है— 'सुविधाएं चाहिए, तो टैक्स समय पर देना होगा।'

विकास का सीधा कनेक्शन

उपायुक्त डॉ. सचिन बांगर ने स्पष्ट किया कि यह 243 करोड़ केवल सरकारी आंकड़ा नहीं है, बल्कि शहर की सड़कों, पानी की आपूर्ति और स्वच्छता को बेहतर बनाने का 'फ्यूल' है। जितना अधिक कर जमा होगा, नागरिकों को उतनी ही गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सकेंगी।

31 मार्च की डेडलाइन

नगर निगम ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे 31 मार्च 2026 से पहले अपने सभी बकाये का भुगतान कर दें ताकि उन्हें कानूनी कार्रवाई या अतिरिक्त ब्याज से न जूझना पड़े। यह संग्रह न केवल निगम को वित्तीय मजबूती देगा, बल्कि आने वाले साल के लिए विकास योजनाओं का रोडमैप भी तैयार करेगा।

ठाणे-बेलापुर मार्ग पर अब नहीं रुकेगा पहिया

रबाले, पावणे और तुर्भे में बनेंगे फ्लाईओवर

पाम बीच मार्ग पर बनेगी डबल टनल

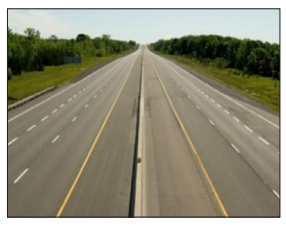

डीबीडी संवाददाता । नवी मुंबई

नवी मुंबई के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण ठाणे-बेलापुर मार्ग को पूरी तरह सिग्नल-मुक्त बनाने की दिशा में नवी मुंबई नगर निगम ने एक बड़ा कदम उठाया है। महासभा में रबाले से तुर्भे तक फ्लाईओवर और डबल अंडरग्राउंड टनल (भुयारी मार्ग) बनाने के ऐतिहासिक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत रबाले, पावणे और तुर्भे जैसे व्यस्त जंक्शनों पर नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। सबसे खास आकर्षण पाम बीच मार्ग पर महापालिका मुख्यालय के पास बनने वाली 'डबल अंडरग्राउंड टनल' होगी। इससे वाहन चालकों को बिना किसी सिग्नल पर रुके ठाणे से बेलापुर तक का सफर तय करने में आसानी होगी। नगर निगम पर एक साथ वित्तीय बोझ न पड़े, इसके लिए 30:70 का मॉडल अपनाया गया है। 30% प्रोजेक्ट शुरू होने और निर्माण के दौरान दिया जाएगा। 70% प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अगले 10 वर्षों में किस्तों में चुकाया जाएगा।

क्यों पड़ी इस प्रोजेक्ट की जरूरत?

नवी मुंबई में अटल सेतु (MTHL) के शुरू होने और नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम अंतिम चरण में होने के कारण वाहनों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। वाशी और ऐरोली खाड़ी पुलों से आने वाला ट्रैफिक ठाणे-बेलापुर रोड पर भारी जाम का कारण बनता है। भविष्य के इसी दबाव को झेलने के लिए यह प्रोजेक्ट अनिवार्य बताया गया है। सदन में इस प्रस्ताव पर तीखी बहस भी हुई। शिवसेना के द्वारकानाथ भोईर और विजय चौगुले ने प्रोजेक्ट की कुल लागत और तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति को लेकर पारदर्शिता की मांग की। विपक्ष का तर्क था कि इतने बड़े प्रोजेक्ट का विवरण (Details) सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि फंड के सही इस्तेमाल पर नजर रखी जा सके।

दो मासूमों से दरिंदगी आरोपी गिरफ्तार

डीबीडी संवाददाता । भिवंडी

भिवंडी में मानवता को शर्मसार करने वाली दो अलग-अलग घटनाएं सामने आई हैं, जहां दो नाबालिग लड़कियों के साथ हैवानियत की गई। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों मामलों के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट ने उन्हें 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

पहली घटना: डरा-धमकाकर किया शोषण

पहली घटना शांतिनगर स्लम एरिया की है। आरोप है कि अमजद बालवन (24) नाम के युवक ने 15 फरवरी को एक 15 साल की किशोरी को बहला-फुसलाकर सैलून के पीछे एक कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने उससे बात करना बंद कर दिया, तो आरोपी उसे घर वालों को फोन करने और इंस्टाग्राम पर बदनाम करने की धमकी देने लगा। पीड़िता ने हिम्मत दिखाकर 22 मार्च को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

दूसरी घटना: रक्षक ही बना भक्षक

दूसरी झकझोर देने वाली घटना भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक सोसाइटी में हुई। यहाँ सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले 58 वर्षीय वॉचमैन (शाहिद इद्रीस मोमिन) ने उसी अपार्टमेंट में रहने वाली महज 10 साल की मासूम को अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ यौन अत्याचार किया। बच्ची की माँ की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज

दोनों ही मामलों में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (दुष्कर्म), 74 और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 4, 8, 12 के तहत मामला दर्ज किया है। पॉक्सो एक्ट विशेष रूप से बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है, जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान है। भिवंडी न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों को 27 मार्च 2026 तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है।

नागरिक समस्याओं पर शिवसेना की चेतावनी

कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की तैयारी

डीबीडी संवाददाता । उल्हासनगर

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) ने शहर में बढ़ती नागरिक समस्याओं को लेकर प्रशासन को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। पार्टी नेताओं ने सड़कों की खुदाई, यातायात जाम, जल आपूर्ति, पुनर्वास और कचरा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर तत्काल ठोस कार्रवाई की मांग करते हुए मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। चेतावनी दी गई है कि समस्याओं का समाधान नहीं होने पर लोकतांत्रिक तरीके से तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा।

अमृत योजना-2 के तहत शहर में चल रहा भूमिगत सीवरेज कार्य तय समय सीमा के बावजूद अधूरा है। मानसून नजदीक होने के कारण जगह-जगह खुदाई से जलभराव और बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। शिवसेना ने कार्यों की पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है।

शिव मंदिर क्षेत्र से करीब 30 परिवारों को बिना पूर्व सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था के हटाए जाने का आरोप लगाया गया है। इसे अमानवीय बताते हुए प्रभावित परिवारों के तत्काल पुनर्वास की मांग की गई है।

यातायात व्यवस्था चरमराई, जांच की मांग

शहर में बस सेवा शुरू होने के बावजूद सड़कों की खुदाई के कारण यातायात बाधित है। कुछ यातायात पुलिसकर्मियों पर कर्तव्य में लापरवाही के आरोप भी लगाए गए हैं। मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। सेंचुरी कंपनी से जुड़े 11 करोड़ रुपए के टैक्स मामले की जांच पूरी होने के बाद उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग भी शिवसेना ने उठाई है, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

कचरा प्रबंधन पर उठे सवाल

शहर में कचरा प्रबंधन का जिम्मा कोनार्क कंपनी को दिए जाने के बावजूद कई इलाकों में कचरे के ढेर लगे होने की शिकायत है। कचरा उठाने वाले वाहनों और कर्मचारियों के कामकाज पर सवाल उठाते हुए व्यवस्था सुधारने की मांग की गई है। सड़क चौड़ीकरण के दौरान सड़कों पर ही पुरानी कारों की दुकानें, गैरेज और अन्य व्यवसाय संचालित होने से ट्रैफिक जाम बढ़ रहा है। शिवसेना ने ऐसे अतिक्रमणों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

प्रशासन को अंतिम चेतावनी

शिवसेना प्रतिनिधिमंडल ने कल्याण जिला प्रमुख शरद पाटिल समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ मनपा आयुक्त मनीषा अवहाले से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने स्पष्ट किया कि यदि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ, तो नागरिकों के हित में बड़ा जनआंदोलन किया जाएगा।

गैस की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

आयुक्त सौरभ राव ने लिया स्टॉक का जायजा

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के हालातों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की अनिश्चितता को देखते हुए ठाणे महानगरपालिका अलर्ट मोड पर है। मेयर शर्मिला पिंपलोलकर और मनपा आयुक्त सौरभ राव ने शहर में गैस सिलेंडर की सप्लाई और पाइपलाइन गैस की स्थिति की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। खाड़ी देशों में तनाव के कारण भविष्य में गैस सप्लाई प्रभावित होने की आशंका है। इसे देखते हुए आयुक्त सौरभ राव ने HP, BP और इंडियन ऑयल के नोडल अधिकारियों के साथ मौजूदा स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का रिव्यू किया। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ठाणे के घरेलू और कमर्शियल ग्राहकों को सिलेंडर के लिए भटकना न पड़े।

मेयर और आयुक्त ने पुलिस की विशेष शाखा और जिला आपूर्ति अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शहर में कहीं भी गैस की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई एजेंसी या वेंडर कृत्रिम किल्लत पैदा कर ऊंचे दामों पर सिलेंडर बेचता पाया गया, तो उसका लाइसेंस रद्द करने के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि कुछ इलाकों में पाइपलाइन गैस के कनेक्शन 4 से 5 साल से पेंडिंग हैं। मेयर ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि जिन सोसाइटियों में मंजूरी मिल चुकी है, वहां तुरंत सप्लाई शुरू की जाए।

छोटे व्यापारियों के लिए नई नीति

एचपी गैस की नोडल अधिकारी चित्रा नायर ने बताया कि सिलेंडर की प्रतीक्षा सूची कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। छोटे व्यापारियों और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए गैस सप्लाई के संबंध में शासन स्तर पर बातचीत चल रही है। सरकार से निर्देश मिलते ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

स्थानीय पार्षदों के जरिए शिकायतों का निपटारा

आयुक्त ने निर्देश दिया कि स्थानीय नगरसेवकों के पास आने वाली गैस संबंधी शिकायतों को इकट्ठा कर सीधे कंपनियों को भेजा जाए। गैस कंपनियों को एक निश्चित टाइमलाइन (समय सीमा) दी जाएगी, जिसके भीतर उन्हें उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करना होगा।

कहाँ खो गई मेरी ट्विंकल?

आठ महीने से लापता बेटी की तलाश में भटकता एक परिवार, उम्मीद अब भी जिंदा

विनय दूबे । भाईंदर

भाईंदर (पूर्व) के नवघर इलाके में रहने वाले उपाध्याय दंपति के लिए बीते आठ महीने किसी अंतहीन अंधेरे से कम नहीं हैं। उनकी 33 वर्षीय बेटी भारती उर्फ 'ट्विंकल' 29 जुलाई 2025 से लापता है। समय बीतता जा रहा है, लेकिन नवघर पुलिस अब तक उसका कोई सुराग नहीं लगा सकी है। घर का एक कोना आज भी उसकी राह देख रहा है—खामोश, सूना और उम्मीद से भरा। कुर्ला में एक छोटी सी पान की टपरी चलाकर परिवार का गुजारा करने वाले राजेश उपाध्याय की आंखों में थकान जरूर है, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी है। हर मिलने वाले से उनका एक ही सवाल होता है-'साहब, मेरी बेटी कहाँ है?' उनकी बूढ़ी आंखों में हर दिन एक नई उम्मीद जन्म लेती है, कि शायद आज कोई खबर मिले, शायद आज ट्विंकल लौट आए।

भारती ने केवल आठवीं तक पढ़ाई की थी और उसके बाद अचानक पढ़ाई छोड़ दी। तभी से वह खुद में सिमट गई थी। न किसी से ज्यादा बात, न कोई दोस्त, न ही बाहर की दुनिया से कोई खास जुड़ाव। वह मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी नहीं करती थी, जिससे सोशल मीडिया की दुनिया से भी पूरी तरह अनजान थी। दिनभर घर में रहना और पास के बजरंगबली मंदिर में जाना—बस यही उसकी दिनचर्या थी।

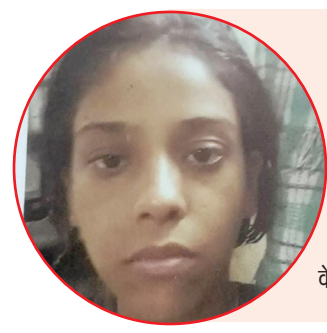

मंदिर गई और फिर कभी वापस नहीं आई

29 जुलाई 2025 की सुबह भी हर दिन की तरह सामान्य थी। ट्विंकल मंदिर जाने के लिए घर से निकली, लेकिन उस दिन के बाद वह कभी वापस नहीं लौटी। परिवार ने हर संभव जगह तलाश की, रिश्तेदारों से लेकर आसपास के इलाकों तक—लेकिन हर कोशिश नाकाम रही।

पुलिस जांच पर उठे सवाल

इस मामले में स्थानीय भाजपा नेता और भाईंदर (पूर्व) मंडल के युवा अध्यक्ष रवि मिश्रा ने भी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि यदि जांच में लापरवाही नहीं बरती जाती, तो शायद आज भारती का कोई सुराग मिल चुका होता। उन्होंने नवघर पुलिस थाने की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मामले में तेजी लाने की मांग की है। समय चाहे जितना बीत जाए, एक पिता का दिल हार मानने को तैयार नहीं होता। राजेश उपाध्याय आज भी हर दिन अपनी दुकान पर बैठते हुए उसी उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि किसी दिन उनकी बेटी दरवाजे पर दस्तक देगी और कहेगी 'पापा, मैं आ गई'

बीमार मां और टूटा हुआ परिवार

इस सदमे ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। भारती की मां पहले से ही गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं। बेटी के गुम होने के बाद उनकी हालत और भी बिगड़ गई है। उपाध्याय दम्पति को एक बेटा और एक बेटी है। उनकी बड़ी बेटी का ससुराल भाईंदर में है, इसलिए लगभग डेढ़ साल पहले राजेश उपाध्याय अपने परिवार के साथ बेटी के पड़ोस में रहने भाईंदर आ गए थे। किराये के छोटे से घर में रहने वाला यह परिवार अब सिर्फ एक उम्मीद के सहारे जी रहा है कि उनकी ट्विंकल एक दिन वापस आएगी।

महाराष्ट्र के गांवों में ही मिलेगा 'स्मार्ट' रोजगार

- विधान परिषद में कौशल विश्वविद्यालय विधेयक मंजूर
- लातूर और पुणे में खुलेंगे दो नए हाई-टेक संस्थान

देवेंद्रनाथ जैस्वार । मुंबई

महाराष्ट्र विधान परिषद ने राज्य के युवाओं को स्कौशलयुक्त और रोजगारक्षमस बनाने के लिए निजी कौशल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में और कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा की पहल पर लाया गया यह विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले पलायन को रोकने में काफी हद तक सहायक साबित होगा।

स्थानीय स्तर पर रोजगार और पलायन पर रोक

कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने स्पष्ट किया कि इन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को उनके अपने जिले या गांव के पास ही उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देना है। जब युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही उद्योगों की जरूरत के हिसाब से स्किल मिलेगी, तो उन्हें रोजगार के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। विधान परिषद में पारित होने के बाद अब यह विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया जाएगा। वहां से पारित होते ही इन दोनों संस्थानों के संचालन का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। यह कदम प्रधानमंत्री के 'स्किल इंडिया मिशन' को जमीनी स्तर पर उतारने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।

लातूर में पर्यावरण और मीडिया का संगम

लातूर में पाशा पटेल स्किल टेक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। यह संस्थान केवल पारंपरिक पढ़ाई नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण जैसे गंभीर विषयों पर डिग्री और प्रैक्टिकल कोर्स कराएगा। इसके साथ ही, ग्रामीण युवाओं को मीडिया मैनेजमेंट, ब्रांडिंग और विज्ञापन के क्षेत्र में भी माहिर बनाया जाएगा।

पुणे में बैंकिंग और AI का नया हब

पुणे स्थित 'FUEL स्किल टेक एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी' आधुनिक तकनीक पर केंद्रित होगी। यहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। यह विश्वविद्यालय युवाओं को केवल नौकरी के लिए नहीं, बल्कि उद्यमी बनने के लिए भी तैयार करेगा।

सरकारी खजाने पर जीरो बोझ

इन विश्वविद्यालयों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये स्व-वित्तपोषित होंगे। यानी इनके निर्माण और संचालन के लिए राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। निजी संस्थाएं खुद निवेश करेंगी, जिससे सरकार का पैसा बचेगा और युवाओं को बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा।

संजय गांधी नेशनल पार्क में शिकार का आरोप

- तीर-कमान से वन्यजीवों को निशाना बनाने का दावा

मुंबई। संजय गांधी नेशनल पार्क में जंगली जानवरों के शिकार को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। शिवसेना (उद्धव) नेता आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि पार्क में तीर-कमान (धनुष-बाण) से खुलेआम शिकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी तस्वीरें आई हैं, जिनमें वन्यजीवों को धनुष-बाण से निशाना बनाया गया है, और इसे लेकर तत्काल सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आदित्य ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि जब धनुष-बाण गलत हाथों में होगा, तो ऐसी घटनाएं सामने आएंगी। उन्होंने वन विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राष्ट्रीय उद्यान जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियां बेहद चिंताजनक हैं और वन्यजीवों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा करती हैं।

बीकेसी में फर्जी पुलिस रेड कर 12 लाख की ठगी

सस्ते कपड़ों का झांसा देकर बुलाया मुंबई

मुंबई। देश के प्रमुख बिजनेस हब बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में ठगी का हाई-प्रोफाइल मामला सामने आया है। सात शातिरों के गिरोह ने फर्जी पुलिस रेड का नाटक रचकर नागपुर के कपड़ा व्यापारी से 12 लाख रुपये ठग लिए। घटना के बाद बीकेसी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, वहीं कारोबारी जगत में दहशत का माहौल है। पुलिस के अनुसार, गिरोह ने बेहद योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया। चार आरोपी खुद को पुलिसकर्मी बताकर मौके पर पहुंचे और रेड का माहौल बना दिया, जबकि उनके साथियों ने पहले ही व्यापारी से नकदी अपने कब्जे में ले ली थी।

पीड़ित निलेश गायकवाड़ नया गारमेंट कारोबार शुरू करने की तैयारी में थे। दिल्ली में उनकी मुलाकात साहिल नामक युवक से हुई, जिसने उन्हें निहाल बंसल से मिलवाया। बंसल ने सस्ते दाम पर कपड़े देने का झांसा देकर पूरी डील नकद में तय कराई। 18 मार्च को गायकवाड़ 12 लाख रुपये लेकर मुंबई पहुंचे और निर्देशानुसार रकम रोहन अग्रवाल को सौंप दी। गायकवाड़ और उनके साथियों को बीकेसी बुलाया गया, जहां एक इनोवा कार से उतरे चार लोगों ने खुद को पुलिस बताकर रेड शुरू कर दी। अचानक की इस कार्रवाई से घबराकर व्यापारी कुछ समझ पाते, उससे पहले आरोपी मौके से फरार हो गए।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

मुख्य अभियंता (ठोस कचरा प्रबंधन)

प्रोजेक्ट नंबरः Ch.Eng/5783/SWM/Project, दिनांक 23.03.2026

ई-टेंडर सूचना

बृहन्मुंबई महानगरपालिका के आयुक्त निम्नलिखित ई-टेंडर आमंत्रित करते हैं:-

कार्य का नाम	अनुबंध अवधि	EMD (जमानत राशि)	टेंडर स्क्रूटनी फीस	बिड शुरू होने की तिथि व समय	बिड समाप्ति की तिथि व समय
देवनार डंपिंग ग्राउंड में MS पोर्टा सिक्योरिटी केबिन एवं उसके संबंधित उपकरणों की आपूर्ति व स्थापना तथा 10x20x10 आकार की RCC चौकी को तोड़ना। **टेंडर आईडी: 2026_MCGM_1289442**	LOA/ SAP P.O. प्राप्त होने की तारीख से 45 दिन (जो पहले हो)।	13,500/- (ऑनलाइन भुगतान www.maha-tenders.gov.in पर)	3630/- + GST 18% = 4283/- (ऑनलाइन भुगतान www.ma-hatenders.gov.in पर)	25.03.2026, सुबह 11:00 बजे के बाद	01.04.2026, शाम 4:00 बजे तक

टेंडर की कॉपी महाटेंडर्स पोर्टल (http://mahatenders.gov.in) के "tender" सेक्शन से डाउनलोड की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए http://mahatenders.gov.in पर लॉग इन करें।

पीआरओ/3377/विज्ञा./2025-26

हस्ता/-
कार्यकारी अभियंता (SWM) प्रोजेक्ट – देवनार

समय पर उपचार, बचाएं प्राण।

पश्चिम रेलवे

स्पेयर ब्रिज मस्त लगाने का कार्य

मुंबई सेंट्रल (मुंबई–400008) के वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (Sub) **ई-निविदसंख्या: WR-MMCTOESUB(ESOT)/23/2025 (RT) तारीख: 18.03.2026 आमंत्रित करते हैं । कार्य का नाम:** चर्चगेट – विरार सेक्शन में स्पेयर ब्रिज मस्त लगाना अनुमानित लागतः 60,94,086/- **बिड सुरक्षा (EMD):** 1,21,900/- **टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि:** 16.04.2026, दोपहर 3:00 बजे तक टेंडर खोलने का समयः 16.04.2026, दोपहर 3:30 बजे अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें: **www.ireps.gov.in** 1249

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

पंप आउट करने हेतु स्लज डीजल पंप प्रदान करना

मंडल रेल प्रबंधक (WA), पश्चिम रेलवे, 6वीं मंजिल, इंजीनियरिंग विभाग, मुंबई सेंट्रल, मुंबई 400008, **ई-टेंडर नोटिस संख्या: BCT/25-26/352, दिनांक 20.03.2026 आमंत्रित करते हैं। कार्य एवं स्थान:** विरार–जोरवासन सेक्शनः विभिन्न स्थानों पर मानसून के पानी को निकालने हेतु स्लज डीजल पंप उपलब्ध कराना, RUB's पर LC 44, 45, 46, 50, 53, 54, 59, 63, 65 (कुल 09 संख्या) ADEN/ DRD सेक्शन के अंतर्गत तथा RUB's नंबर 68, 72, 78, 89, ब्रिज 229, LC नंबर 347A वापी सबवे, और भिलाड RUB (कुल 08 संख्या) ADEN/वलसाड सेक्शन के अंतर्गत। **कार्य की अनुमानित लागत:** 32,60,878.30 EMD: 65,200/- **जमा करने की तिथि एवं समय:** 14.04.2026 को 15:00 बजे तक **खोलने की तिथि एवं समय:** 14.04.2026 को 15:30 बजे तक अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइटः www.ireps.gov.in देखें। 1250

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

ई-नीलामी कार्यक्रम में संशोधन

सामग्री प्रबंधन विभाग

ई-नीलामी बिक्री सूचना क्रमांक S III /Auction Programme-1/APRIL-2026 दिनांक 09/03/2026 के संबंध में यह संशोधन जारी किया जाता है। अप्रैल 2026 महीने के लिए आयोजित की जाने वाली नीलामियों के संबंध में निम्नलिखित परिवर्तन किया गया है. अप्रैल 2026 के लिए वेस्टर्न रेलवे के सभी डिपो और डिवीजनों में प्रस्तावित पहली चरण (First Round) की सभी नीलामियां रद्द (Cancelled) कर दी गई हैं। अन्य सभी शर्तें और नियम पूर्ववत (जैसे के तैसे) रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप निम्न वेबसाइट देख सकते हैं: पश्चिम रेलवे की वेबसाइटः wr.indianrailways.gov.in ई-ऑक्शन पोर्टलः www.ireps.gov.in (संख्या: SIII/Auction Programme-2/APRIL 2026, दिनांक 23/03/2026) 1255

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

मध्य रेल

निविदा के लिए सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, मुंबई मण्डल (मध्य रेल) द्वारा योग्य निविदाकारों से कसारा स्टेशन पर केटरिंग स्टाल हेतु खुली ई-निविदाओं रमेश को आमंत्रित करते हैं। **कार्य का नाम -** मुंबई मंडल में जनरल माइनर यूनिट KSRA-S-2 (GMU) के अंतर्गत कैटरिंग स्टॉल की व्यवस्था, सामान्य श्रेणी महिला कोटा के अंतर्गत "C" श्रेणी स्टेशन पर, डबल पैकेट प्रणाली के तहत प्लेटफॉर्म संख्या 1 एवं 2 (नए FOB, CSMT छोर) पर 5 वर्षों की अवधि के लिए। निम्न विवरण के अनुसार:-

यूनिट का नाम	निविदा नंबर	स्टेशन का नाम/श्रेणी	स्थान	स्टाल श्रेणी
KSRA-S-1	BBC159COCA TGKSR A-S-1-2026	कसारा स्टेशन श्रेणी "एसजी2" (पुरानी श्रेणी "सी")	प्लाट फॉर्म क्रमांक 4, बुकिंग ऑफिस के किनारे, इगतपुरी की तरफ	सामान्य श्रेणी महिला कोटा'

कार्य समाप्ति की अवधि: 05 (पांच) वर्ष; **वेबसाईट विवरण:** www.ireps.gov.in
ई निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय: दिनांक 08/04/2026 को 15.00 बजे तक;
अधिक जानकारी हेतु संपर्क करने का कार्यालय :- वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय, रेलवे आरक्षण केंद्र के ऊपर, खानन अनुभागपा, मुंबई सीएसएमटी - 400 001;

यह नोटिस केवल निविदा विज्ञापन उद्देश्य के लिए है, विस्तृत नियम और शर्तें निविदा दस्तावेज में उपलब्ध हैं। इसके अलावा परिशिष्टशुद्धिपत्र/, समय विस्तार, स्पष्टीकरण आदि, यदि कोई हो, विषय निविदा के संबंध में, केवल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। बोलीदाताओं को खुद को अपडेट रखने के लिए नियमित रूप से वेबसाइट पर जाना चाहिए। रेलवे पूर्णया भाग में कार्य को स्वीकार करने या बिना किसी कारण बताए पूर्ण या भाग में निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सशर्त प्रस्तावों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

सहायक वाणिज्य प्रबंधक (आरक्षण)
(कृते) वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक, सी एस एम टी

रेल्वे फाटक को बंध स्थिति में पार करना मना है। 1017

मध्य रेल

विभिन्न व्यावसायिक संपत्तियों को लीज पर देने के लिए ई-नीलामी

मुंबई मंडल, मध्य रेलवे ने ई-निलामी लीजिंग मॉड्यूल के माध्यम से www.ireps.gov.in पर नीचे दी गई संपत्तियों कि लीजिंग के लिए ई-नीलामी का आह्वान किया है । **इच्छुक बोली दताओंको ई-निलामी लीजिंग मॉड्यूल में पंजीकृत होना आवश्यक है और ई-निलामी से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे** / अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाताओ से अनुरोध है की नीचे उल्लिखित ई-निलामी के विवरण जानने के लिए वेबसाइट www.ireps.gov.in देखें:

सं.	श्रेणी	उप-श्रेणी	निलामी प्रारंभ तिथि
1	विज्ञापन	ट्रेनों के अंदर एवं बाहरी मोबाइल एसेट्स	27.03.2026, 28.03.2026, 02.04.2026
		आरडीएन (RDN)	25-03-2026, 26.03.2026,
		ओओएच (OOH)	24.03.2026, 30.03.2026, 31.03.2026
2	पे एंड पार्किंग	मिश्रित पार्किंग	25.03.2026, 27.03.2026, 30.03.2026, 31.03.2026, 02.04.2026
3	पे एंड यूज़	कलवा स्टेशन	27.03.2026
4	पार्सल	27FRSLR, 11SLR	24.03.2026, 01.04.2026
5	कैटरिंग	वेटिंग रूम सह कैंटीन (NGSM, TPND गुड्स, कलंबोली गुड्स, कल्याण)	25.03.2026, 31.03.2026, 01.04.2026, 02.04.2026, 06.04.2026
		डीआर (DR) पर मुलती पर्पज़ स्टॉल	01.04.2026
6	अन्य गैर-किराया राजस्व (NFR)	टीएनए (TNA) और रोहा (ROHA) में वेटिंग रूम	26.03.2026
		केवाईएन से केजेटी-खोपोली एवं केवाईएन से कसारा सेक्शन में उपभोग्य एवं गैर-उपभोग्य वस्तुओं की वेंडिंग	01.04.2026
		डीआर (DR) और एमएई (MAE) में मसाज चेयर	27.03.2026
		पीएन वी एल और केवाईएन मैं डिजिटल लॉकर	28.03.2026
		डोंबिवली और ठाकुर्ली स्टेशन के बिच 52 चॉल क्षेत्र में गेमिंग ज़ोन सुविधा	02.04.2026
		एलटीटी (LTT) और एमएनकेडी (MNKD) में मोबाइल एक्सेसरीज़ कियोस्क	30.03.2026
		वीएसडी (2 locations VSD), एमएनकेडी (MMKD) और एलटीटी (LTT) में किराना व फोटोकॉपी कियोस्क	31.03.2026, 06.04.2026

इसके अलावा विषय नीलामी के संबंध में, परिशिष्ट/शुद्धिपत्र, लॉट/कैटलॉग की वापसी, नीलामी की तिथि या समय में परिवर्तन, विस्तार, स्पष्टीकरण आदि, यदि कोई हो, केवल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। बोलीदाताओं को स्वयं को अद्यतन रखने के लिए नियमित रूप से वेबसाइट पर जाना चाहिए।

-/DRM(C)CSMT

रेल्वे फाटक को बंध स्थिति में पार करना मना है। 1014

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

वृक्ष प्राधिकरण

– सार्वजनिक सूचना –

महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1975 (जनवरी 2018 संशोधित) की धारा 8(3)(क) के अनुसार **परिमंडल 1 के 'डी' विभाग** से 1 प्रस्ताव, 'ई' विभाग से 1 प्रस्ताव तथा **परिमंडल 2 के 'जी/उत्तर' विभाग** से 1 प्रस्ताव, ऐसे कुल 3 प्रस्तावों को मनपा आयुक्त एवं वृक्ष प्राधिकरण समिति की मंजूरी मिल गई है।

इन प्रस्तावों में पेड़ों को काटने या पुनःरोपण (ट्रांसप्लांट) करने से संबंधित जानकारी है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी मनपा की वेबसाइट **www.mcgm.gov.in** पर उपलब्ध है। संबंधित प्रस्ताव क्रमांकः 'डी' (1096), 'ई' (1097), 'जी/उत्तर' (1098)

उद्यान अधीक्षक एवं वृक्ष अधिकारी
वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान एवं प्राणिसंग्रहालय,
दूसरी मंज़िल, हम्बोल्ट पेंगुइन कक्ष,
संत सावता माली मार्ग, भायखला (पूर्व), मुंबई – 400027
दूरभाषः 23742162 ई-मेलः sg.gardens@mcgm.gov.in

पीआरओ/3387/विज्ञा./2025-26

हस्ता/-
उद्यान अधीक्षक एवं वृक्ष अधिकारी

समय पर उपचार, बचाएं प्राण।

पश्चिम रेलवे

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, मुंबई सेंट्रल मंडल, पश्चिम रेलवे, मंडल रेल प्रबंधक, वाणिज्य विभाग, NFR सेक्शन, मुंबई सेंट्रल, मुंबई – 400 008।

कार्यः मुंबई मंडल में विभिन्न NFR माध्यमों के माध्यम से विज्ञापन का प्रदर्शन।

नीलामी कैटलॉग संख्या	नीलामी प्रारंभ (सभी लॉट)
MMCTADVTMB25-13	10-04-26, 12:00:00

क्र. सं.	लॉट नंबर	स्थान/क्षेत्र	दिन	ई-नीलामी की समाप्ति तिथि और समय
1	MMS-MobGen-133732-2-26-1 (Misc-Mobile-Services-Mobile General)	ट्रेन नंबर 12009/12010 Shatabdi Express, मुंबई सेंट्रल – अहमदाबाद – मुंबई सेंट्रल, पश्चिम रेलवे के मुंबई मंडल में ऑनबोर्ड फ्री लाइफस्टाइल मैगजीन के वितरण का अनुबंध।	1096	10-04-26 12:30:00

नीलामी कैटलॉग संख्या	नीलामी प्रारंभ (सभी लॉट)
MMCT-PnU-25-20	10-04-26, 13:00:00

क्र. सं.	लॉट नंबर	स्थान/क्षेत्र	दिन	ई-नीलामी की समाप्ति तिथि और समय
1	PnU-BCT-MMCT-WRL-80-25-1 (Pay and Use - Lounges/Waiting /Retiring/Cloak Rooms)	Mumbai Central railway station स्टेशन पर रिटायरिंग रूम / डॉरमेट्री के नवीनीकरण, संचालन और रखरखाव के लिए ई-नीलामी।	1826	10-04-26, 13:30:00

नीलामी कैटलॉग संख्या	नीलामी प्रारंभ (सभी लॉट)
MMCT-ADVTM25-61	10-04-26, 14:00:00

क्र. सं.	लॉट नंबर	स्थान/क्षेत्र	दिन	ई-नीलामी की समाप्ति तिथि और समय
1	MSS-BCT-MRU-MedStn-45-24-1 (Misc-Static-Services Medical facilities at station)	Matunga Road railway station पर इमरजेंसी मेडिकल रूम के माध्यम से 5 वर्षों की अवधि के लिए 24 घंटे चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना।	1826	10-04-26 14:30:00
2	MSS-BCT-GTR-MedStn-94-25-1 (Misc-Static-Services Medical facilities at station)	Grant Road railway station पर इमरजेंसी मेडिकल रूम के माध्यम से 5 वर्षों की अवधि के लिए 24 घंटे चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना।	1826	10-04-26 14:40:00
3	MSS-BCT-BDTS-MedStn-93-25-1 (Misc-Static-Services Medical facilities at station)	Bandra Terminus railway station पर इमरजेंसी मेडिकल रूम के माध्यम से 5 वर्षों की अवधि के लिए 24 घंटे चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना।	1826	10-04-26 14:50:00
4	MSS-BCT-RMAR-MedStn-92-25-1 (Misc-Static-Services Medical facilities at station)	Ram Mandir railway station पर इमरजेंसी मेडिकल रूम के माध्यम से 5 वर्षों की अवधि के लिए 24 घंटे चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना।	1826	10-04-26 15:00:00

नीलामी कैटलॉग संख्या	नीलामी प्रारंभ (सभी लॉट)
MMCT-ADVT-25-84	10-04-26, 15:00:00

क्र. सं.	लॉट नंबर	स्थान/क्षेत्र	दिन	ई-नीलामी की समाप्ति तिथि और समय
1	ADVT-Int-S1-EMU15car-357-26-1 (Advertising - Train Interior)	मुंबई मंडल, पश्चिम रेलवे में 15 कोच वाली 10 EMU रेक में अंदर के पैनल और रूट मैप के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित करना, अवधि 5 वर्ष।	1826	10-04-26 15:30:00
2	ADVT-Int-133732-5-26-1 (Advertising - Train Interior)	फैक्ट्री-फिटेड डिजिटल स्क्रीन (कुल 10 स्क्रीन) के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित करने का अनुबंध। ये स्क्रीन ट्रेन नंबर 12009/12010 Shatabdi Express के तीन कोच में लगी हैं—दो विस्टा डोम कोच (प्रत्येक में 4 स्क्रीन) और एक अनुभूति कोच (2 स्क्रीन), MMCT डिवीजन में, अवधि 3 वर्ष।	1096	10-04-26 15:40:00
3	ADVT-BCT-CCG-OH-469-26-1 (Advertising - Out of Home)	Churchgate railway station के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की दीवारों (रोड साइड की ओर) पर LCD/LED के माध्यम से विज्ञापन दिखाने के लिए बल्क एडवरटाइजिंग अधिकार, अवधि 5 वर्ष।	1826	10-04-26 15:50:00

संपर्क विवरण: लैंडलाइन नंबर: 02267644212 ईमेल आईडी: acmadvtgbct@gmail.com
नोट: इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे IREPS वेबसाइट (www.ireps.gov.in) पर ई-ऑक्शन लीजिंग मॉड्यूल पर विजिट करें। वहां दिए गए कैटलॉग के अंतर्गत लॉट-वार विवरण उपलब्ध हैं। 1252

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फालो करें: X.com/WesternRly

ढोंगी बाबा पर 6 महीने से चुप क्यों थे मुख्यमंत्री : सपकाल

मुंबई/बुलढाणा। महाराष्ट्र की राजनीति में अशोक खरात (ढोंगी बाबा) मामले और सतारा जिला परिषद चुनाव को लेकर विपक्ष ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखे हमले किए हैं। बुलढाणा में मीडिया से बात करते हुए हर्षवर्धन सपकाल ने सरकार की मंशा और पुलिसिया कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सपकाल ने दावा किया कि मुख्यमंत्री को अशोक खरात के काले कारनामों की भनक दिवाली (अक्टूबर-नवंबर 2025) के आसपास ही लग गई थी। गृह विभाग सबूत भी जुटा रहा था, लेकिन कार्रवाई मार्च 2026 में हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले को जानबूझकर लटकाया गया ताकि सहयोगियों को दबाव में रखा जा सके। रूपाली चाकणकर के इस्तीफे का जिक्र करते हुए उन्होंने मांग की कि खरात से जुड़े हर रसूखदार व्यक्ति पर मामला दर्ज हो। सपकाल ने कहा कि महाराष्ट्र अंधविश्वास उन्मूलन कानून बनाने वाला पहला राज्य है, फिर भी खरात जैसे लोग पैदा हो रहे हैं। उन्होंने डॉ. नरेंद्र दाभोलकर के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि जब तक समाज में वैज्ञानिक सोच नहीं आएगी और धर्म-जाति के नाम पर नफरत फैलाई जाएगी।

शंभूराज देसाई और मकरंद पाटिल के साथ बदसलूकी लोकतंत्र का पतन

सतारा जिला परिषद चुनाव के दौरान मंत्री शंभूराज देसाई और मकरंद पाटिल के साथ हुई पुलिसिया धक्का-मुक्की को सपकाल ने लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में मंत्री ही पुलिस से पिट रहे हैं, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा? इस घटना ने चुनावों में 'वोट चोरी' और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों को सच साबित कर दिया है।

गायकवाड पर भी बरसे सपकाल

विधायक संजय गायकवाड को घेरते हुए सपकाल ने कहा कि क्षेत्र में विकास के नाम पर केवल ठेकेदारी का खेल चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध रेत उत्खनन और मटका जैसे धंधों से करोड़ों की संपत्ति बनाई गई है। कार्यकर्ताओं के पास फॉर्च्यूनर और विधायक के पास करोड़ों की डिफेंडर गाड़ी कहाँ से आई, इसकी जांच होनी चाहिए।

'श्वेतपत्रिका' की मांग

सपकाल ने सरकार से मांग की है कि बुलढाणा और संबंधित क्षेत्रों में खर्च किए गए हर रुपये का हिसाब जनता के सामने रखा जाए। उन्होंने भ्रष्टाचार को 'अशोक खरात' जैसी ही एक सामाजिक विकृति बताया, जो अंदर ही अंदर लोकतंत्र को खोखला कर रही है।

मछुआरों के नुकसान की भरपाई के लिए बनेगा स्पेशल स्टडी ग्रुप

- नितेश राणे ने दिए एक महीने में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश
- माहिम के मछुआरों को भी मिलेगा वर्ली जैसा मुआवजा

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

मुंबई की महत्वाकांक्षी वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक परियोजना के कारण प्रभावित होने वाले मछुआरों के लिए राहत की खबर है। मंगलवार को मंत्रालय में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में मछुआरों के नुकसान की भरपाई और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे नितेश राणे ने अधिकारियों को एक विशेष स्टडी ग्रुप बनाने का निर्देश दिया है। यह समूह वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक परियोजना के कारण मछुआरों को होने वाले वास्तविक नुकसान का वैज्ञानिक और जमीनी आकलन करेगा। इस ग्रुप को एक महीने के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट और समाधान सरकार को सौंपने होंगे।

एमएमआरडीए को सख्त निर्देश

यह परियोजना मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से पूरी की जा रही है। नितेश राणे ने स्पष्ट किया कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शहर के लिए जरूरी हैं, लेकिन इसका खामियाजा उन मछुआरों को नहीं भुगतने दिया जाएगा जिनकी रोजी-रोटी समंदर पर निर्भर है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तकनीकी बारीकियों के साथ मानवीय संवेदनाओं का भी ध्यान रखें।

मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का संकल्प

बैठक में याद दिलाया गया कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पहले ही मछुआरों को उचित न्याय दिलाने का वादा किया था। सरकार का रुख साफ है कि विकास की इस दौड़ में पारंपरिक मछुआरा समुदायों के हितों की रक्षा करना प्राथमिकता है। यवतमाल में कोलाम समाज के 'लॉन्ग मार्च' और अन्य प्रभावित वर्गों के आंदोलनों के बीच सरकार अब किसी भी समुदाय की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती।

संपादकीय

हरीश राणा और इच्छामृत्यु की नैतिक जद्दोजहद

गाजियाबाद के हरीश राणा का शांत होना महज एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं है, बल्कि यह उस लंबी कानूनी और भावनात्मक लड़ाई का विराम है, जिसने भारत में 'सम्मान के साथ मरने के अधिकार' (Right to Die with Dignity) की बहस को फिर से जीवंत कर दिया है। 13 साल का लंबा इंतजार, कोमा की गहरी खामोशी और बिस्तर पर सिमटा हुआ एक नौजवान जीवन—हरीश की कहानी करुणा, संघर्ष और अंततः एक कठिन मुक्ति की दास्तान है। वर्ष 2013 में रक्षाबंधन के दिन, जिस भाई को अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेना था, वह नियति के क्रूर मजाक का शिकार होकर चौथी मंजिल से गिर गया। 'क्वाड्रिप्लेजिया' ने न केवल उनके शरीर को जकड़ा, बल्कि उनके परिवार के सपनों को भी उम्रकैद दे दी। हरीश के माता-पिता के लिए यह फैसला लेना कि उनके बेटे को अब 'जाने दिया जाए', दुनिया का सबसे भारी निर्णय रहा होगा। जब दिल्ली हाईकोर्ट ने 2025 में उनकी याचिका खारिज की, तो वह कानून की नजर में एक प्रक्रिया थी, लेकिन एक मां-बाप के लिए वह अपने बच्चे के असहनीय दर्द को और खींचने जैसा था। 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट का पैसिव यूथेनेशिया (निष्क्रिय इच्छामृत्यु) की अनुमति देना भारतीय न्यायिक इतिहास में एक मील का पत्थर है। अस्पताल के गलियारे में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ती मां की छवि उस अंतहीन उम्मीद का प्रतीक है, जो विज्ञान के हारने के बाद भी टिकी रहती है। इच्छामृत्यु को लेकर पूरी दुनिया दो धड़ों में बंटी हुई है। नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे देशों ने 2002 में सक्रिय इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता दी थी। वर्तमान में कनाडा, कोलंबिया, लक्ज़मबर्ग, स्पेन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सभी राज्यों में सक्रिय इच्छामृत्यु या सहायता प्राप्त मृत्यु (Assisted Dying) के विभिन्न प्रावधान लागू हैं। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली जैसे देशों में 'असिस्टेड सुसाइड' की अनुमति है, जहाँ मरीज डॉक्टर की देखरेख में स्वयं दवा लेता है। अमेरिका के 10 राज्यों (जैसे ओरेगन, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन) में भी यह कानून प्रभावी है। इसके उलट, भारत का रुख 'पैसिव यूथेनेशिया' तक सीमित है, जहाँ जीवन रक्षक प्रणाली को हटाया जाता है। आंकड़े बताते हैं कि नीदरलैंड में होने वाली कुल मौतों में से लगभग 4% से 5% मौतें इच्छामृत्यु के जरिए होती हैं, जो वैश्विक स्तर पर एक बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। हरीश राणा के अंतिम छह दिन बिना अन्न-जल के बीते। विज्ञान की भाषा में यह 'चिकित्सीय प्रक्रिया' है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं के धरातल पर यह किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं। समाज के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि जीवन की परिभाषा क्या है? क्या सिर्फ धड़कनों का चलना ही जीवन है, या चेतना और संवाद का होना भी अनिवार्य है? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में स्पष्ट किया था कि ₹मरणासन्न व्यक्ति को गरिमा के साथ मरने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का ही हिस्सा है। हरीश अब शांत हैं। उनकी 13 साल की 'जंग' समाप्त हो चुकी है। यह मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे चिकित्सा तंत्र को 'उपशामक देखभाल' (Palliative Care) पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इच्छामृत्यु का कानून केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि उन परिवारों के प्रति संवेदना का हाथ है जो सालों से अपनों को कष्ट में देखकर तिल-तिल मरते हैं। हरीश की विदाई हमें सिखाती है कि मृत्यु डरावनी नहीं होती, बल्कि गरिमाहीन जीवन का अंतहीन सिलसिला अधिक भयावह होता है।

शख्सियत

फारुख शेख

सादगी के प्रतीक

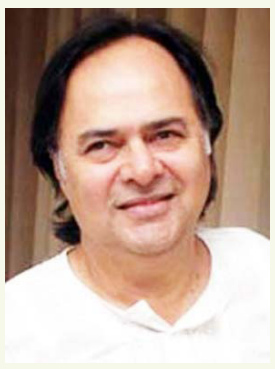

भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ कलाकार ऐसे हुए हैं, जिन्होंने बिना किसी शोर-शराबे या 'लार्जर दैन लाइफ' इमेज के दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। फारुख शेख एक ऐसा ही नाम है, जिन्हें उनकी सहजता, शालीनता और बौद्धिक अभिनय के लिए सदैव याद किया जाएगा।

25 मार्च 1948 को गुजरात के अमरोली में जन्मे फारुख शेख का जीवन न केवल कलाकारों के लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सादगी और सिद्धांतों के साथ सफलता पाना चाहता है। उनके पिता मुस्तफा शेख मुंबई के एक प्रसिद्ध वकील थे। परिवार चाहता था कि फारुख भी वकालत में अपना करियर बनाएं। उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी भी की, लेकिन उनका मन हमेशा से कला और अभिनय में रमता था। कॉलेज के दिनों में वे नाटक और थिएटर से जुड़ गए, जहाँ उनकी मुलाकात शबाना आजमी जैसे कलाकारों से हुई। उनका शुरुआती दौर संघर्षपूर्ण था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी गरिमा से समझौता नहीं किया। 1973 में आई एम.एस. सथ्यू की फिल्म 'गरम हवा' से उन्होंने सिनेमा की दुनिया में कदम रखा। इस फिल्म के लिए उन्हें मात्र 750 रुपये मिले थे, जिसे उन्होंने पांच साल में किस्तों में प्राप्त किया। यह उनके धैर्य और कला के प्रति समर्पण की पहली बड़ी परीक्षा थी। 70 और 80 के दशक में जब बॉलीवुड में मसाला फिल्मों और 'एंग्री यंग मैन' का बोलबाला था, तब फारुख शेख ने 'समानांतर सिनेमा' के जरिए अपनी पहचान बनाई।

'चश्मे बद्दूर', 'साथ-साथ', 'बाजार', 'उमराव जान' और 'कथा' जैसी फिल्मों में उन्होंने एक ऐसे साधारण व्यक्ति का किरदार निभाया, जिससे आम आदमी खुद को जोड़ सकता था।

दीप्ति नवल के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। उनकी फिल्मों की खासियत यह थी कि उनमें कोई दिखावा नहीं होता था। वे संवादों को इतनी सहजता से बोलते थे कि लगता ही नहीं था कि वे अभिनय कर रहे हैं। 'शतरंज के खिलाड़ी' में सत्यजीत रे जैसे महान निर्देशक के साथ काम करना उनकी प्रतिभा का प्रमाण था। फारुख शेख केवल बड़े पर्दे तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने टेलीविजन पर 'जीना इसी का नाम है' जैसे शो की मेजबानी की, जहाँ उनकी तहजीब और बातचीत के लहजे ने लोगों का दिल जीत लिया। इसके अलावा, नाटक 'तुम्हारी अमृता' में उनके अभिनय ने विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त की। यह नाटक 20 से अधिक वर्षों तक चलता रहा, जो उनके निरंतर कौशल का प्रतीक है।

फारुख शेख के जीवन का सबसे प्रेरक पहलू उनकी गुमनाम दानशीलता थी। उनके निधन के बाद कई ऐसी कहानियाँ सामने आईं, जहाँ उन्होंने गरीब छात्रों की शिक्षा और जरूरतमंदों की गुप्त रूप से मदद की थी।

वे कभी भी अपनी नेकदिली का बखान नहीं करते थे। वे एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने ग्लैमर की दुनिया में रहकर भी अपनी जड़ों और संस्कारों को कभी नहीं छोड़ा। 27 दिसंबर 2013 को फारुख शेख दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनका काम आज भी प्रासंगिक है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सफलता के लिए चिल्लाने या चमक-धमक की आवश्यकता नहीं होती। यदि आपके पास हुनर है, भाषा पर पकड़ है और व्यवहार में विनम्रता है, तो आप लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं। फारुख शेख का व्यक्तित्व उस पुरानी दुनिया की तहजीब की याद दिलाता है, जहाँ इंसान की पहचान उसके काम और उसके चरित्र से होती थी।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

महिला सशक्तिकरण की ऐतिहासिक पहल

धीरज सिंह
समाचार संपादक

भारत में महिलाओं की आबादी लगभग आधी है, लेकिन उनकी राजनीतिक भागीदारी हमेशा कम रही है। लोकसभा में वर्तमान में महिलाओं की संख्या कुल सदस्यों का लगभग 14 से 15 प्रतिशत ही है। यह संख्या कई अन्य देशों की तुलना में भी कम है। ऐसे में यह अधिनियम महिलाओं को आगे लाने और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत में महिलाओं को राजनीति में समान अवसर देने के उद्देश्य से बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। लंबे समय से यह मांग उठती रही कि देश की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को लाया गया, जिसे आम भाषा में महिला आरक्षण कानून भी कहा जाता है। यह कानून भारत के लोकतंत्र को अधिक मजबूत और समावेशी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

इस अधिनियम के अनुसार, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी। इसका मतलब है कि हर तीन सीटों में से एक सीट महिला उम्मीदवार के लिए होगी। यह आरक्षण केवल सामान्य वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्गों में भी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। इस तरह यह कानून समाज के सभी वर्गों की महिलाओं को राजनीति में भाग लेने का अवसर देता है। भारत में महिलाओं की आबादी लगभग आधी है, लेकिन उनकी राजनीतिक भागीदारी हमेशा कम रही है। लोकसभा में वर्तमान में महिलाओं की संख्या कुल सदस्यों का लगभग 14 से 15 प्रतिशत ही है। यह संख्या कई अन्य देशों की तुलना में भी कम है। ऐसे में यह अधिनियम महिलाओं को आगे लाने और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है।

महिला आरक्षण का विचार नया नहीं है। पहली बार यह प्रस्ताव 1996 में संसद में लाया गया था। उसके बाद कई बार इसे पेश किया गया, लेकिन राजनीतिक सहमति के अभाव में यह पारित नहीं हो सका। 2010 में यह राज्यसभा से पास भी हो गया था, लेकिन लोकसभा में अटक गया। अंततः वर्षों के लंबे इंतजार और बहस के बाद इसे "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" के रूप में पारित किया गया। यह इस बात का संकेत है कि अब देश महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए तैयार है। हालांकि, इस अधिनियम को लागू करने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। इसे लागू करने से पहले देश में नई जनगणना और उसके आधार पर परिसीमन (सीटों का नया बंटवारा) किया जाएगा। इसके बाद ही यह आरक्षण पूरी तरह लागू हो सकेगा। यही कारण है कि कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं

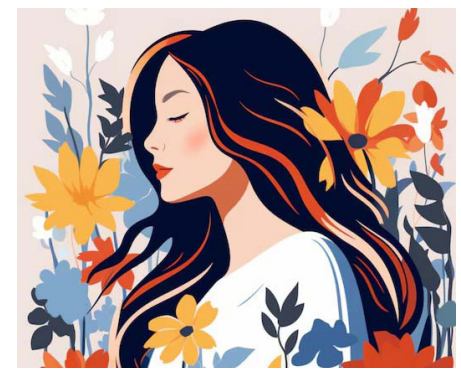

और कहते हैं कि इसका फायदा तुरंत नहीं मिलेगा। फिर भी, यह एक सकारात्मक शुरुआत मानी जा रही है। इस अधिनियम के कई महत्वपूर्ण लाभ हैं। सबसे पहला लाभ यह है कि महिलाओं की संख्या संसद और विधानसभाओं में बढ़ेगी। इससे महिलाएं अपने विचार और समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगी। दूसरा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला सुरक्षा और बच्चों के विकास जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। तीसरा, यह समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता की भावना को बढ़ावा देगा। इसके अलावा, यह अधिनियम नई पीढ़ी की लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा। जब वे देखेंगी कि महिलाएं संसद में जाकर देश के महत्वपूर्ण फैसले ले रही हैं, तो उनमें भी आगे बढ़ने की इच्छा पैदा होगी। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगी।

हालांकि, इस अधिनियम के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग है। कुछ राजनीतिक दलों का कहना है कि इस कानून में OBC महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा, सीटों के रोटेशन (हर चुनाव में सीट बदलना) की व्यवस्था भी एक चिंता का विषय है। इससे कुछ नेताओं को यह डर है कि उनकी सीट अगली बार आरक्षित हो सकती है, जिससे उनका राजनीतिक भविष्य प्रभावित हो सकता है।

इन चुनौतियों के बावजूद, यह अधिनियम भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पंचायत और नगर निकायों में पहले से ही महिलाओं के लिए आरक्षण लागू है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। वहां महिलाओं ने अपनी नेतृत्व क्षमता साबित की है और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए अब यह व्यवस्था संसद और विधानसभाओं में भी लागू की जा रही है। अंत में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक कानून नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के अधिकार, सम्मान और समान भागीदारी की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन है। यह अधिनियम यह संदेश देता है कि महिलाएं भी देश के विकास में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं जितनी पुरुष निभाते हैं। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया, तो यह भारत की राजनीति और समाज दोनों में एक नई दिशा और नई सोच लेकर आएगा।

इस प्रकार, नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को सशक्त बनाने, समाज में समानता स्थापित करने और देश के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है।

हमारी गीता

स्वप्न से सत्य की ओर

स्वामिनी निष्कलानंदा
चिन्मय मिशन कल्याण

अर्जुन अपनी बुद्धिमानी दिखाकर जब स्वयं भगवान को ही तत्वज्ञान दे रहा था, तब भगवान ने उसे अनदेखा किया और मौन रहे। परंतु, जब भावनाविवश होकर वह कायरतापूर्ण कृति करने लगा, तब करुणासागर भगवान बिना बुलाए ही उसकी सहायता के लिए आते हैं। सैन्यदल के सेनापति की आज्ञा के समान भगवान अर्जुन को कह रहे हैं— 'क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप'। अर्थात, अपने हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्यागकर उठो! गीता उपनिषदों का सार है। भगवान यहाँ 'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत' के उपनिषद मंत्र को ही याद दिला रहे हैं। यही स्वामी विवेकानंद जी का भी अमर संदेश है।

हमें लग सकता है कि हम तो सब कुछ कर ही रहे हैं। कठिन परिश्रम करके धन आदि कमा रहे हैं, जागृत अवस्था में हैं और सोए नहीं हैं, इसलिए हमें 'उत्तिष्ठ जाग्रत' के आदेश की आवश्यकता नहीं है। परंतु, केवल शारीरिक कर्म करना ही जीवन की वास्तविक जागृति नहीं है। हम अपनी कल्पनाओं का स्वप्न जैसा एक संसार रचते हैं और उसी में जीते रहते हैं; इस भ्रमरूपी स्वप्न से बाहर निकलना ही सच्ची जागृति है। 'उत्तिष्ठ' का अर्थ केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठना है। यह अंधकार से प्रकाश की ओर, दुख से सुख की ओर, अविद्या से विद्या की ओर और अपयश से यश की ओर उन्नत होने की प्रक्रिया है। यदि हम लेटे रहेंगे, तो प्रमाद में सो जाएंगे। 'उत्तिष्ठ' का एक गहरा अर्थ है— सावधान होना। यदि हम बैठ जाएंगे तो आलस्य घेरेगा और यदि बिना सोचे-समझे चलेंगे तो गिरने का भय रहेगा। सावधान स्थिति में खड़े

रहकर ही हम सजगता के साथ सुयोग्य कर्म कर सकते हैं। अपनी स्थिति, कौशल, परिस्थिति और कर्मफल का सावधानीपूर्वक विचार करके कर्म में प्रवृत्त होना ही वास्तविक 'उत्तिष्ठ' है। इसे एक उदाहरण से समझें— घर के भीतर रहने पर केवल दीवारें दिखाई देती हैं, लेकिन विमान में बैठने पर संपूर्ण नगर एक दृष्टि में समा जाता है और ऊपर से सब कुछ छोटे बिंदु के समान दिखने लगता है। और अधिक ऊँचाई पर जाने पर केवल अनंत आकाश दिखाई देता है। जीवन में ऊपर की ओर जाने का अर्थ है सूक्ष्म को पहचानना। संकुचित नाली से निकलकर महासागर में तैरना ही विस्तार है। हमें 'मैं और मेरा' के सीमित जीवन से बाहर आना होगा। संकुचित विचारधारा ही वह क्षुद्रता है जो हमें दुर्बल बनाती है।

जीवन ऊर्जा

निर्भीक पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 1890 में हुआ था। उन्होंने अपने समाचार पत्र 'प्रताप' के माध्यम से अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाई और गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी। साम्प्रदायिक सद्भाव के प्रबल समर्थक विद्यार्थी जी ने 25 मार्च 1931 को कानपुर दंगों में लोगों की जान बचाते हुए मानवता के लिए अपना बलिदान दे दिया।

गणेश शंकर विद्यार्थी : निधन : 25 मार्च 1931

अवसान

विश्वास पर भविष्य की इमारत खड़ी होती है।

समय की कद्र करने वाला ही इतिहास रचता है। प्रकृति के रहस्यों को केवल आंखों से नहीं बल्कि तर्क की गहराई से समझना चाहिए क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में छिपी संपदा समाज की प्रगति का आधार है। अनुशासन ही अन्वेषण की पहली सीढ़ी है। ज्ञान वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाता है। सच्ची विद्वत्ता वही है जो मानवता के काम आए। समाज तभी फलता-फूलता है जब विज्ञान और नैतिकता साथ चलते हैं। धातुओं का शोधन केवल तकनीक नहीं बल्कि धैर्य की परीक्षा है। चरित्र का निर्माण भी संघर्ष की भट्ठी में होता है और सत्य की जीत सुनिश्चित होती है। कठिन परिश्रम ही सफलता का एकमात्र मार्ग है। जो व्यक्ति प्रकृति का सम्मान करता है वही उसके रहस्यों को प्राप्त कर पाता है क्योंकि ब्रह्मांड के नियम अटल हैं। एकता में ही शक्ति है। समाज का ढांचा आपसी सहयोग पर टिका है और हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण होता है। विचार ही कार्यों की जननी होते हैं। अनुभवों से सीखना ही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। परिवर्तन संसार का नियम है और अनुकूलन ही अस्तित्व की कुंजी है। जिज्ञासा ही आविष्कार की जननी है। बिना साहस के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि डर प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु है। ईमानदारी ही सबसे बड़ी नीति है। न्यायप्रिय समाज ही दीर्घजीवी होता है जहाँ शिक्षा का उद्देश्य केवल जीविका नहीं बल्कि जीवन का निर्माण होना चाहिए। प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हमारे कार्यों का परिणाम भोगेंगी। निस्वार्थ सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। शांति और सद्भाव ही विश्व कल्याण का मार्ग हैं। अंततः सत्य की ज्योति ही संपूर्ण जगत को आलोकित करती है, जिससे मानवता का मार्ग प्रशस्त होता है। सच्ची देशभक्ति निस्वार्थ सेवा में निहित है। पत्रकारिता समाज का दर्पण होनी चाहिए जिसे सत्य के मार्ग से कभी नहीं डिगना चाहिए।

सर्वसिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ बिजाना शाजापुर मध्यप्रदेश

क्रोध: विवेक का शत्रु और पश्चाताप का द्वार

मनुष्य के भीतर छिपे विकारों में क्रोध सबसे भयानक और विनाशकारी माना गया है। नीतिशास्त्रों में कहा गया है कि 'क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणाम्', अर्थात क्रोध मनुष्य के शरीर में स्थित उसका पहला और सबसे बड़ा शत्रु है। यह एक ऐसा क्षणिक पागलपन है, जो व्यक्ति की सोचने-समझने की शक्ति को हर लेता है और उसे ऐसे कृत्यों की ओर धकेल देता है, जिनका परिणाम केवल और केवल पश्चाताप होता है। क्रोध की उत्पत्ति अज्ञानता से होती है और इसका अंत हमेशा आत्मग्लानि के साथ होता है। इस संदर्भ में एक पौराणिक कथा अत्यंत प्रासंगिक है। एक समय की बात है, एक राजा घने जंगल में शिकार खेलते हुए अपने दल से बिछड़ गया। चिलचिलाती धूप और लंबी दूरी तय करने के कारण राजा प्यास से व्याकुल हो उठा। उसे दूर-दूर तक पानी का कोई स्रोत दिखाई नहीं दे रहा था। प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था और शरीर शिथिल पड़ता जा रहा था। तभी उसकी नजर एक विशाल वृक्ष पर पड़ी, जिसकी एक टहनी से टप-टप करती पानी की कुछ बूंदें गिर रही थीं।

पंडित कैलाशचंद्र शर्मा
वैदिक सनातन संस्कृति के प्रचारक व सर्व सिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ के संस्थापक।
मो. नं. 9425980556

राजा ने धैर्यपूर्वक पत्तों का एक दोना बनाया और उन बूंदों को इकट्ठा करने लगा। बूंदें बहुत धीरे गिर रही थीं, इसलिए दोना भरने में काफी समय लगा। जब बड़ी मशक्कत के बाद दोना भर गया और राजा ने जैसे ही उसे पीने के लिए अपने होठों से लगाया, तभी कहीं से उड़कर आए एक तोते ने जोर से 'टें-टें' की आवाज की और दोने पर झपट्टा मार दिया। सारा पानी नीचे गिर गया। राजा को दुख तो हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी और दोबारा दोना भरने लगा। काफी समय बाद जब दोबारा दोना भरा और राजा ने उसे उठाया, तो उसी तोते ने फिर से झपट्टा मारकर पानी गिरा दिया।

अब राजा के धैर्य का बांध टूट गया। तीव्र

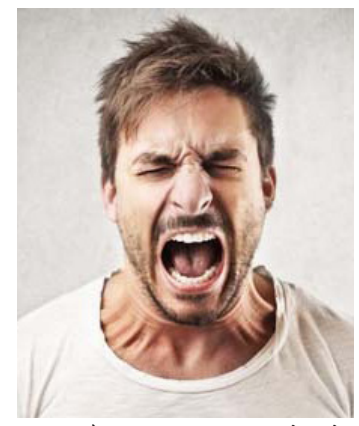

प्यास और बार-बार की बाधा ने उसे क्रोध के वशीभूत कर दिया। उसने सोचा कि यह दुष्ट पक्षी जानबूझकर मुझे प्यासा मारना चाहता है। क्रोध में अंधे होकर राजा ने अपना चाबुक निकाला और जैसे ही तीसरी बार तोता झपट्टा मारने आया, राजा ने उस पर प्राणघातक प्रहार कर दिया। निर्दोष पक्षी के प्राण पखेरू वहीं उड़ गए।

पक्षी को मारने के बाद राजा ने सोचा कि बूंद-बूंद पानी इकट्ठा करने के बजाय क्यों न सीधे स्रोत से ही पानी पी लिया जाए। वह वृक्ष के ऊपर उस डाली के पास पहुंचा जहां से पानी टपक रहा था। वहां का दृश्य देखते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उस डाली पर एक भयंकर विषैला अजगर सोया हुआ था और उसके मुंह से जो लार टपक रही थी, जिसे राजा पानी समझ रहा था, वह वास्तव में काल के समान घातक विष था।

राजा की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसे समझ आया कि वह पक्षी उसका शत्रु नहीं, बल्कि परम हितैषी था जो अपनी जान जोखिम में डालकर उसे जहर पीने से बचा रहा था। राजा ने विलाप करते हुए कहा, ₹काश! मैंने संतों के बताए क्षमा के मार्ग को अपनाया होता और अपने क्रोध पर नियंत्रण किया होता, तो आज इस बेगुनाह की जान न जाती।₹ यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध में व्यक्ति केवल दूसरों का ही नहीं, बल्कि स्वयं का भी भारी नुकसान कर बैठता है। क्रोध वह जहर है जिसे हम स्वयं पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मर जाए। जो व्यक्ति कठिन समय में संयम और क्षमा को धारण करता है, वही वास्तव में वीर कहलाता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी भावनाओं का दास न बनकर उनका स्वामी बने। इसलिए, जीवन में जब भी क्रोध की स्थिति बने, तो कुछ पल रुककर विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एक क्षण का मौन भविष्य के वर्षों के पश्चाताप को टाल सकता है।

अपने विचार

मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ दो राउंड फोन पर बात की है. हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार बातें कर रहे हैं. हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं. हमारा उद्देश्य, डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है।

–नरेंद्र मोदी
प्रधान मंत्री, भारत

हमने तय किया कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम काम करेंगे। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई सरपरस्त क्यों न हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो ये मानकर चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट कटा रहा है।

–योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

अब नीतीश सरकार ने तय किया है कि कैमूर के अधौरा पहाड़ पर हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएगी।सबसे खूंखार आतंकवादी होंगे, उन्हें यहां बंद किया जाएगा। इसे ऐसी पहाड़ी पर बनाया जाएगा, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं आएगा और इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं होगी।

–सम्राट चौधरी
उप मुख्यमंत्री, बिहार

युवाओं को केवल डिग्री तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी जड़ों से भी जुड़ना होगा। 'कल्चरल क्लब' इसी सोच का परिणाम है। यह मंच छात्रों को अपनी पहचान समझने, अपनी कला को अभिव्यक्त करने और दूसरों की संस्कृति का सम्मान करना सिखाता है।

–जयवीर सिंह
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री

अपने विचार

डीबीडी कार्यालय

ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के.के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई-400001
indiagroundreport@gmail.com
भेज सकते हैं।

यह अखबार "माध्यम कार्पोरेट सर्विसेज लि." के लिए प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक अरुण लाल द्वारा ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के. के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001 से प्रकाशित एवं सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नं. 4, एन.के.इंडस्ट्रियल इस्टेट, इनसाइड प्रवासी इंडिस्ट्रयल इस्टेट गेट नं. 2, गोरेगांव पू., मुंबई-63 से मुद्रित. फोन नं. 022-66555719 ईमेल : indiagroundreport@gmail.com कार्यकारी संपादक : अमित बृज (पी.आर.बी. अधिनियम के अंतर्गत खबरों के चयन के लिए ज्मिेदार).

ब्रीफ न्यूज़

पश्चिम रेलवे द्वारा 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

मुंबई। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरों को विस्तारित किया गया है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेन संख्या 09622 बांद्रा टर्मिनस–अजमेर स्पेशल को 27 अप्रैल, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09621 अजमेर–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को 26 अप्रैल, 2026 तक विस्तारित किया गया है। ट्रेन संख्या 04828 बांद्रा टर्मिनस–भगत की कोठी स्पेशल को 12 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 04827 भगत की कोठी–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को 11 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। ट्रेन संख्या 09706 बांद्रा टर्मिनस–जयपुर स्पेशल को 13 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09705 जयपुर–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को 12 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। ट्रेन संख्या 04728 वलसाड–हिसार स्पेशल को 16 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 04727 हिसार–वलसाड स्पेशल को 15 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

30 मार्च को राजस्थान महोत्सव का भव्य आयोजन

ठाणे। राजस्थान विकास मंच के तत्वाधान में 30 मार्च 2026 को राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में 'राजस्थान महोत्सव' का भव्य और धूमधाम से आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन की विस्तृत रूपरेखा और तैयारियों की जानकारी साझा करने के लिए मंच द्वारा 25 मार्च 2026, बुधवार को होटल वुडलैंड में एक पत्रकार परिषद (प्रेस कॉन्फ्रेंस) बुलाई गई है। यह प्रेस वार्ता दोपहर 1:00 बजे से 2:30 बजे तक आयोजित की जाएगी, जिसमें महोत्सव के आगामी कार्यक्रमों और सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में आधिकारिक घोषणा की जाएगी।

सेंचुरी रेयॉन प्रीमियर क्रिकेट लीग 2026: 'ब्रह्मोश' टीम ने जीता खिताब

उल्हासनगर। सेंचुरी रेयॉन कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में 15 और 22 मार्च 2026 को आयोजित 'सेंचुरी रेयॉन प्रीमियर क्रिकेट लीग (सीआरसीपीएल)' का रोमांचक समापन हुआ, जिसमें 'ब्रह्मोश' टीम ने अपनी शानदार रणनीति और टीम वर्क के दम पर खिताबी जीत दर्ज की। यूनिट प्रमुख दिग्विजय पांडे के मार्गदर्शन में संपन्न हुई इस प्रतियोगिता में कुल आठ टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 'फैंटम' और 'सेंचुरी स्ट्राइकर्स' ने भी क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त कर कड़ा मुकाबला पेश किया। आधुनिक तकनीक के माध्यम से यूट्यूब पर प्रसारित इस टूर्नामेंट में व्यक्तिगत और टीम प्रदर्शन के लिए कुल 23 पुरस्कार वितरित किए गए।

महाराष्ट्र की सड़कों पर दौड़ेगी राजमाता जिजाऊ स्मार्ट बस

मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपनी गौरवशाली परंपरा में एक नया और आधुनिक अध्याय जोड़ते हुए 'राजमाता जिजाऊ' स्मार्ट बस सेवा का शानदार आगाज़ किया है। मंगलवार (24 मार्च 2026) को विधानभवन परिसर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने ढोल-ताशों और लेझीम की गूँज के बीच इस सेवा का लोकार्पण किया। यह बस सेवा केवल एक वाहन नहीं, बल्कि राजमाता जीजाबाई की प्रेरणादायी विरासत को समर्पित है। बस के अगले हिस्से (अग्रभाग) में राजमाता जीजाबाई की भव्य प्रतिमा लगाई गई है, जो यात्रियों को महाराष्ट्र के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाती है। उद्घाटन के दौरान खुद मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने बस में सफर कर इसकी सुविधाओं का जायजा लिया।

3,000 बसों का विशाल बेड़ा

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने घोषणा की है कि इस योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में 3,000 नई स्मार्ट बसें चलाई जाएंगी। यह अभियान महाराष्ट्र के दूर-दराज के इलाकों को मुख्य शहरों से जोड़ने और यात्रियों को एक मानक (Standard) यात्रा अनुभव देने के लिए शुरू किया गया है।

सुरक्षा, तकनीक और आराम के साथ महाराष्ट्र के गौरव का प्रतीक

'स्मार्ट बस' होने के नाते ये गाड़ियाँ आधुनिक तकनीक से लैस हैं। इनमें CCTV कैमरे, रियल-टाइम लोकेशन ट्रैकिंग (GPS), पैनिक बटन और मोबाइल चार्जिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं। सुरक्षा और विश्वसनीयता के उच्च मानकों को ध्यान में रखते हुए इनका डिजाइन तैयार किया गया है। MSRTC की प्रीमियम 'शिवनेरी' और 'शिवशाही' सेवाओं की सफलता के बाद, 'राजमाता जिजाऊ' सेवा को एक नई श्रेणी के रूप में पेश किया गया है। इसका उद्देश्य मध्यम वर्गीय और आम यात्रियों को कम खर्च में लक्ज़री और आराम का अनुभव कराना है, ताकि वे निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें।

विकास का स्मार्ट पहिया

मुख्यमंत्री फडणवीस ने इसे महाराष्ट्र के विकास का अनोखा संगम बताया। इस सेवा के शुरू होने से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। यह बस सेवा राज्य के परिवहन विभाग के लिए एक 'गेम-चेंजर' साबित हो सकती है।

कपास खरीद अवधि बढ़ाने की मांग

केंद्र से राज्य सरकार ने किया आग्रह

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

प्रदेश में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का पूरा लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से कपास खरीद की अवधि बढ़ाने की मांग की है। विधान परिषद में विपणन मंत्री जयकुमार रावल ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों से अब तक 137 लाख क्विंटल कपास की खरीद की जा चुकी है, जिसकी कुल कीमत 10,883 करोड़ रुपये है।

खरीद केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी

सदन में नियम 97 के तहत विधायक संजय खोडके द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में मंत्री रावल ने बताया कि इस वर्ष 168 कपास खरीद केंद्रों को मंजूरी दी गई थी, जो पिछले साल के 128 केंद्रों से अधिक है। इनमें से 162 केंद्रों पर सक्रिय रूप से कपास की खरीद की जा चुकी है।

अवधि बढ़ाने से बढ़ी खरीद

मंत्री ने बताया कि पहले कपास खरीद की अंतिम तिथि 15 फरवरी थी, जिसे बढ़ाकर 15 मार्च किया गया। इस अतिरिक्त अवधि में 9.90 लाख क्विंटल कपास की और खरीद की गई। उन्होंने कहा कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए अब केंद्र सरकार से एक बार फिर खरीद अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

सिंहस्थ कुंभ के लिए रेलवे का 'ट्रैक' तैयार

डीबीडी संवाददाता । नासिक

आगामी सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 (14 जुलाई से 25 सितंबर 2027) की तैयारियों को लेकर भारतीय रेलवे ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नाशिक जिले के नारायणगांव (निफाड) में रेलवे विस्तार के लिए जरूरी भूमि अधिग्रहण और हस्तांतरण की प्रक्रिया मंगलवार को सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। मौजे नारायणगांव (तालुका निफाड) में रेलवे परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण पूरी तरह से पारदर्शी और विधिसम्मत तरीके से किया गया। यह स्थानीय प्रशासन, रेलवे के भुसावल मंडल के अधिकारियों और ग्रामवासियों के बीच उत्कृष्ट समन्वय का परिणाम है।

नारायणगांव में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया संपन्न
25 किसानों के सहयोग से मिली ज़मीन

किसानों का सहयोग

इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए कुल 3 सर्वे नंबरों (गट क्रमांक 657, 658, 659) की भूमि अधिग्रहित की गई है। इसमें कुल 25 किसानों और भू-स्वामियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। रेलवे प्रशासन ने इन सभी किसानों के प्रति आभार व्यक्त किया है, जिनके सकारात्मक सहयोग के कारण यह राष्ट्रीय महत्व का कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हुआ। इस अधिग्रहित भूमि का उपयोग रेलवे स्टेशनों के अपग्रेडेशन और नई आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए किया जाएगा। इसका सीधा लाभ उन लाखों श्रद्धालुओं को मिलेगा जो 2027 में नाशिक और त्र्यंबकेश्वर पहुँचेंगे। इससे यात्रा सुरक्षित, तीव्र और सुविधाजनक होगी। अधिग्रहण प्रक्रिया का समापन कुंभ मेले के दौरान भीड़ प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेगा। रेलवे की क्षमता बढ़ने से न केवल परिवहन सुधरेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

दिव्यांग कल्याण विभाग में अब एमपीएससी से होगी भर्ती

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

राज्य में दिव्यांग कल्याण योजनाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे ने विधानसभा में बताया कि विभाग में अधिकारियों की भर्ती अब महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) के माध्यम से की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्द ही नियुक्तियां शुरू होने की संभावना है।

कौशल विकास पर विशेष फोकस

राज्य सरकार 18 से 45 वर्ष के दिव्यांगों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चला रही है। वर्तमान में 110 स्किल और उद्यमिता विकास केंद्रों में 1000 से अधिक लाभार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

अधूरे दस्तावेजों के लिए विशेष अभियान

जिन लाभार्थियों के दस्तावेज अधूरे हैं, उनके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक दिव्यांग योजनाओं का लाभ उठा सकें। मंत्री ने स्पष्ट किया कि दिव्यांग कल्याण योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

जिला स्तर पर मजबूत होगा प्रशासनिक ढांचा

मंत्री सावे ने कहा कि विभाग को स्वतंत्र बनाने के बाद अब जिला स्तर पर प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। चयनित अधिकारियों का प्रशिक्षण जारी है और ट्रेनिंग पूरी होते ही उन्हें नियमित रूप से तैनात किया जाएगा, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।

वार्ड 72 में पानी संकट पर धरना

भाजपा नेता पंकज यादव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन
बीएमसी ने दिया समाधान का आश्वासन

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

के-ईस्ट वार्ड के वार्ड क्रमांक 72 में पानी की गंभीर समस्या को लेकर पंकज यादव ने स्थानीय नागरिकों के साथ धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में वर्षों से जल संकट बना हुआ है, जिससे लोगों को रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कई बार महानगरपालिका के जल विभाग के अधिकारियों से बातचीत भी की, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला।

पानी आपूर्ति में कमी और भेदभाव का आरोप

पंकज यादव के अनुसार के-ईस्ट वार्ड में लगभग 490 एमएलडी पानी की जरूरत है, जबकि वर्तमान में केवल 480 एमएलडी पानी ही उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सीमित आपूर्ति में भी वार्ड 72 के हिस्से में कटौती की जा रही है, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। इससे पहले नगरसेविका ममता पंकज यादव ने भी लिखित रूप से जल आपूर्ति सुधारने की मांग उठाई थी, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।

बीएमसी का आश्वासन, आंदोलन की चेतावनी

धरने के बाद बृहन्मुंबई महानगरपालिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक कर जल्द पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। हालांकि पंकज यादव ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ, तो वे जल विभाग के शीर्ष अधिकारियों के कार्यालय के बाहर बड़ा आंदोलन करेंगे।

सिविल हॉस्पिटल में 30 दिन का 'ओरल हेल्थ अवेयरनेस' अभियान शुरू

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के अवसर पर ठाणे सिविल हॉस्पिटल में 20 मार्च से 30 दिनों का विशेष ओरल हेल्थ अवेयरनेस अभियान शुरू किया गया। "एक हेल्दी मुंह पूरी हेल्थ की नींव है" संदेश के साथ शुरू इस पहल का उद्देश्य जिलेभर में लोगों को दांतों और मुंह की साफ-सफाई के प्रति जागरूक करना है। अभियान का उद्घाटन हेल्थ डायरेक्टर डॉ. नितिन अंबाडेकर ने किया। इस दौरान सिविल सर्जन डॉ. कैलाश पवार, अतिरिक्त सिविल सर्जन डॉ. धीरज महानगड़े, डॉ. अर्चना पवार और डॉ. शुभांगी अंबाडेकर समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे।

रेगुलर चेक-अप और सही आदतों पर जोर

विशेषज्ञों ने बताया कि नियमित डेंटल चेक-अप, संतुलित आहार और सही हाइजीन आदतें दांतों और मसूड़ों की बीमारियों से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका हैं। लोगों को समय-समय पर दांतों की जांच कराने की सलाह दी गई। डॉक्टरों ने कहा कि दांत और मसूड़ों से जुड़ी समस्याओं को अक्सर लोग हल्के में लेते हैं, जबकि इनका असर पूरे शरीर की सेहत पर पड़ सकता है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य इसी जागरूकता को बढ़ाना है।

डेमोंस्ट्रेशन और मुफ्त जांच की सुविधा

अभियान के दौरान जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सही तरीके से ब्रश करने और मुंह की सफाई बनाए रखने का डेमोंस्ट्रेशन दिया जाएगा। साथ ही, आने वाले हर मरीज की दांतों की जांच कर आवश्यक प्राथमिक उपचार भी उपलब्ध कराया जाएगा।

स्कूल-कॉलेजों में भी चलेंगे जागरूकता कार्यक्रम

अभियान के तहत सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न सामाजिक स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खासतौर पर बच्चों को सही तरीके से ब्रश करने की आदत सिखाने पर जोर दिया जाएगा। कैंपेन में मुंह के कैंसर और तंबाकू उत्पादों के नुकसान के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी जाएगी, ताकि लोग समय रहते इन आदतों से दूर रह सकें।

12 राशिफल में देखें अपना दिन

प्रियंका जैन
97699 94439

मेष व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। नेत्र पीड़ा संभव है। विवाद न करें। रोजगार मिलेगा। भेंट व उपहार की प्राप्ति होगी। आपकी मिलनसारिता व धैर्यवान प्रवृत्ति आपके जीवन में आनंद का संचार करेगी। स्थायी संपत्ति में वृद्धि होगी।

वृष सार्वजनिक कार्यों में समय व्यतीत होगा। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। रोजगार के क्षेत्र में उन्नति होगी। कुसंगति से बचें। लेन-देन में सावधानी रखें। शारीरिक कष्ट संभव है। व्ययवृद्धि से तनाव रहेगा। विवाद न करें।

मिथुन दुःखद समाचार मिल सकता है। विरोध होगा। व्यर्थ भागदौड़ होगी। लाभ के अवसर टलेंगे। विवाद न करें। कार्य निर्णय बहुत शांति से विचार करके करना ही शुभ है। स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें। रुका धन मिलेगा।

कर्क वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। यात्रा सफल रहेगी। लाभ होगा। उत्तम मनोबल आपकी सभी समस्याओं को हल कर देगा। प्रतिष्ठित जनों से मेलजोल बढ़ेगा। व्यापार में नए प्रस्ताव मिलेंगे।

सिंह अतिथियों का आगमन होगा। शुभ समाचार मिलेंगे। मान बढ़ेगा। विवाद न करें। आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है। व्यापार में नए अनुबंध होंगे। व्ययों में कमी करना चाहिए। व्यापार अच्छा चलेगा। जीवनसाथी से मतभेद। फालतू खर्च होगा।

कन्या व्यवसाय ठीक चलेगा। परोपकार करके मानसिक सुख अर्जित करेंगे। व्यापारिक स्थिति आशाजनक रहेगी। पारिवारिक, मांगलिक कार्य की योजना बनेगी। कर्ज लेने से बचना चाहिए। परिवार की चिंता रहेगी। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। कानूनी अड़चन दूर होगी।

तुला धर्म-कर्म में रुचि रहेगी। कानूनी अड़चन दूर होगी। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। समाज के कामों में उत्साहपूर्वक भाग लेंगे। नौकरी में तबादला तथा पदोन्नति के योग हैं। अनावश्यक क्रोध न करें। धन संबंधी काम पूरे होंगे।

वृश्चिक आय में कमी रहेगी। धैर्य रखें। स्वास्थ्य की समस्या हल होगी। ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी। जीवनसाथी की भावनाओं को समझें। आर्थिक निवेश लाभकारी रहेगा। पुराना रोग उभर सकता है। चोट, चोरी व विवाद आदि से हानि संभव है।

धनु रोजगार मिलेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा। नवीन गतिविधियां लाभकारी रहेंगी। व्यापार में नई योजनाओं का प्रारंभ होगा। पराक्रम के प्रति निष्क्रियता के कारण मन अप्रसन्न रहेगा। शत्रु परास्त होंगे। भूमि व भवन की खरीद-फरोख्त हो सकती है।

मकर विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। पार्टी व पिकनिक का आनंद मिलेगा। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। रोजगार की चिंता रह सकती है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मानसिक दृढ़ता से निर्णय लेकर कार्य करना चाहिए। व्यापार में लाभकारी परिवर्तन होंगे।

कुंभ सुख के साधन जुटेंगे। प्रयास सफल रहेंगे। मान-सम्मान मिलेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा। प्रसन्नता रहेगी। नौकरी में मनचाही पदोन्नति मिलने के योग बनेंगे। धर्म के कार्यों में रुचि आपके मनोबल को ऊंचा करेगी। अजनबियों पर विश्वास न करें।

मीन नई योजना बनेगी। कार्य का विस्तार होगा। व्यवसाय ठीक चलेगा। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। अपनी वस्तुएं संभालकर रखें। काम के प्रति दृढ़ता से कार्य में अनुकूल सफलता मिल सकेगी। पारिवारिक सुख व धन बढ़ेगा। वाणी संयम आवश्यक है।

शेषनाग कालसर्प दोष का रहस्य, प्रभाव और उससे मुक्ति का गूढ़ मार्ग

प्रियंका जैन
97699 94439

वैदिक ज्योतिष की गहराइयों में कुछ ऐसे योग और दोष वर्णित हैं, जो व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा को गहराई से प्रभावित करते हैं। उन्हीं में से एक अत्यंत चर्चित और प्रभावशाली योग है "शेषनाग कालसर्प दोष"। ज्योतिषाचार्य पं. भरतलाल शास्त्री के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु बारहवें भाव में और केतु छठे भाव में स्थित होते हैं, और इनके बीच सभी ग्रह आ जाते हैं, तब पूर्ण रूप से शेषनाग कालसर्प दोष का निर्माण होता है। यह कोई सामान्य स्थिति नहीं होती, बल्कि यह जीवन में कई गहरे अनुभव और संघर्ष लेकर आती है, जो व्यक्ति को भीतर से बदलने की क्षमता रखते हैं।

इस दोष का नाम "शेषनाग" इसलिए रखा गया है क्योंकि यह ऊर्जा सर्प के समान व्यक्ति के जीवन को चारों ओर से घेर लेती है। पौराणिक रूप से शेषनाग को ब्रह्मांड का आधार माना गया है, लेकिन जब यही ऊर्जा असंतुलित रूप में कुंडली में सक्रिय होती है, तो यह व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक और भौतिक जीवन में अशांति उत्पन्न कर सकती है। सबसे पहले यदि इसके मानसिक और भावनात्मक प्रभावों की बात करें, तो यह दोष व्यक्ति के भीतर एक स्थायी बेचैनी उत्पन्न करता है। मन में बिना कारण चिंता, तनाव और असुरक्षा का भाव बना रहता है। कई बार व्यक्ति को अनिद्रा की समस्या भी घेर लेती है, जिससे उसका मानसिक संतुलन प्रभावित होता है। छोटी-छोटी बातों पर क्रोध आना, दूसरों के प्रति संदेह रखना और स्वयं को असहज महसूस करना इस दोष के प्रमुख संकेत माने जाते हैं। धीरे-धीरे यह स्थिति व्यक्ति के सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करने लगती है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान में कमी आ सकती है।

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह दोष कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। विशेष रूप से पेट से जुड़ी बीमारियां जैसे पाइल्स, फिस्टुला और फिशर जैसी परेशानियां देखी जाती हैं। इसके अलावा अचानक दुर्घटनाएं या शारीरिक आघात की संभावना भी बढ़ जाती है। मानसिक तनाव के कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, जिससे छोटी-छोटी बीमारियां भी गंभीर रूप ले सकती हैं।

आर्थिक जीवन में यह दोष अस्थिरता का कारण बन सकता है। व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयास कर ले, धन टिकता नहीं है या अचानक हानि हो जाती है। कई बार व्यक्ति कर्ज के जाल में फंस जाता है और उसे बाहर निकलने में काफी समय लग जाता है। इसके साथ ही छुपे हुए शत्रु, धोखाधड़ी या विश्वासघात जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। अनावश्यक कानूनी मामलों में उलझना और बिना वजह परेशानियां झेलना भी इस दोष के प्रभावों में शामिल है।

विवाह और संबंधों के क्षेत्र में भी शेषनाग कालसर्प दोष का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। विवाह में देरी होना, सही जीवनसाथी का चयन न हो पाना या वैवाहिक जीवन में लगातार तनाव बने रहना इसके सामान्य परिणाम हैं। कई बार तो स्थिति इतनी जटिल हो जाती है कि संबंध टूटने की कगार तक पहुंच जाते हैं। परिवार में भी आपसी समझ की कमी और विवाद बढ़ने लगते हैं।

इसके अतिरिक्त, जीवन में बार-बार असफलता का अनुभव होना, हर काम में रुकावट आना और प्रयासों के बावजूद अपेक्षित परिणाम न मिलना भी इस दोष का संकेत माना जाता है। कुछ लोगों में विदेश जाने की तीव्र इच्छा होती है, लेकिन बार-बार बाधाएं आती हैं। वहीं, कई व्यक्तियों को सर्पों का डर या उनसे जुड़े स्वप्न भी देखने को मिलते हैं, जो इस दोष की सूक्ष्म ऊर्जा का प्रतीक होते हैं।

न्यूज़ ब्रीफ

नवजात को बेचने वाली नर्स समेत दो गिरफ्तार

नोएडा। बिसरख थाना पुलिस ने पांच दिन की नवजात बच्ची को गोद दिलाने के नाम पर बेचने के मामले में फरार चल रही नर्स और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले इस प्रकरण में अस्पताल की संचालिका सहित तीन आरोपितों को पकड़ा जा चुका है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित अस्पताल का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया है। पुलिस के मुताबिक, 21 मार्च को चाइल्ड हेल्पलाइन से मिली सूचना में नवजीवन अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा बच्ची को अवैध रूप से सौंपने के बदले 2.60 लाख रुपये मांगने का खुलासा हुआ था। जांच के दौरान फरार नर्स पुष्पा रानी और अरुण कुमार की तलाश जारी थी, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले में मानव तस्करी के एंगल से भी जांच आगे बढ़ा रही है।

मोहम्मदाबाद का रिश्वतखोर दरोगा नामजद

फर्रुखाबाद। जिले के मोहम्मदाबाद थाने में तैनात दरोगा सुरेश चाहर के खिलाफ रिश्वतखोरी का मामला दर्ज किया गया है। ग्राम पंचायत निसाई की प्रधान गीता देवी की शिकायत पर एसपी के निर्देश में कोतवाली फतेहगढ़ में भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे की जांच के नाम पर दरोगा ने पैसे वसूले। पुलिस के मुताबिक, दरोगा ने अपने बेटे के खाते में करीब 75 हजार रुपये नकद और यूपीआई के जरिए अलग-अलग तारीखों में ट्रांसफर करवाए। शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए ट्रांजैक्शन साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है। मामले को गंभीर मानते हुए जांच तेज कर दी गई है और दरोगा के निलंबन की भी संभावना जताई जा रही है।

नोएडा के दर्जनभर निजी स्कूलों को बम की धमकी

नोएडा। शहर के करीब एक दर्जन निजी स्कूलों को मंगलवार सुबह ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीमें सक्रिय हो गईं और सभी स्कूलों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। एहतियातन कक्षाएं बंद कर छात्रों को घर भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, रामाज्ञा स्कूल, खेतान पब्लिक स्कूल और फादर एंजल स्कूल समेत कई संस्थानों को धमकी भरे मेल मिले थे।

योगी सरकार ने दी 45 कंपनियों को 2781 करोड़ की सब्सिडी

UP के पास 75000 एकड़ का लैंड बैंक

- निवेश मित्र-3 लांच : सीएम ने हस्तांतरित की छूट की धनराशि
- 62 अन्य कंपनियों को दिया गया लेटर आफ कम्फर्ट

एजेंसी । लखनऊ

उत्तर प्रदेश में निवेश को गति देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 'निवेश मित्र-3' पोर्टल का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कार्यरत कंपनियों को कुल 2781.12 करोड़ रुपये की सब्सिडी ऑनलाइन हस्तांतरित की। साथ ही 45 कंपनियों को प्रोत्साहन राशि दी गई और 62 उद्यमों को लेटर ऑफ कम्फर्ट (LoC) जारी किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश ने निवेश के क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव देखा है और अब राज्य निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद गंतव्य के रूप में स्थापित हो चुका है।

खाद्यान्न उत्पादन में 21% का योगदान

उन्होंने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को प्रदेश की बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 21 प्रतिशत योगदान देता है, जबकि यहां 11 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है।

16 घरेलू, चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट

बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एक्सप्रेस-वे नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है और गंगा एक्सप्रेस-वे के पूर्ण होने के बाद उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी स्थिति में होगा।

'निवेश मित्र-3' सिंगल विंडो सिस्टम

'निवेश मित्र-3' को सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से उद्यमियों को आवेदन से लेकर स्वीकृति तक की सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध होंगी। इसका उद्देश्य निवेश प्रक्रिया को सरल बनाना और अनावश्यक देरी को समाप्त करना है। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक सुरक्षा और श्रम प्रबंधन को लेकर सख्त रुख अपनाने की बात दोहराई। इसके अलावा प्रदेश में 16 घरेलू और 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं, जबकि सात शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है। सड़क संपर्क को भी ब्लॉक स्तर तक मजबूत किया गया है।

उद्योगों को प्रभावित करने वालों की खैर नहीं

सीएम ने कहा, उद्योगों को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा, राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

गैस सिलेंडर विस्फोट से ढह गया मकान भाई-बहन की मौत

एजेंसी । वाराणसी

शहर के लहरतारा-मंडुवाडीह क्षेत्र में मंगलवार सुबह गैस सिलेंडर में रिसाव के बाद हुए जोरदार विस्फोट ने एक मंजिला मकान को ध्वस्त कर दिया। हादसे में मलबे में दबकर भाई-बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए। पुलिस के अनुसार, घटना सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच उस समय हुई जब परिवार के सदस्य खाना बना रहे थे। अचानक हुए धमाके से मकान की छत और दीवारें भरभराकर गिर गईं, जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर पुलिस को सूचना दी। कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया।

ठिकाना बदल रहे दर्जनभर अभियुक्तों पर इनाम

- एसपी चारू निगम ने घोषित किया इनाम, गिरफ्तारी को विशेष टीमें लगाई गईं

एजेंसी । सुलतानपुर

जिले में भूमि विवाद से जुड़ी हिंसा के मामले में पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए फरार 12 आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने बताया कि सभी आरोपी लगातार ठिकाने बदलकर गिरफ्तारी से बच रहे हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। घटना 15 मार्च की है, जब अखंडनगर के कल्याणपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग कर दी थी। गोली लगने से संजय यादव (25) घायल हो गए।

सीओ कादीपुर के खिलाफ हुई जांच

वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की। मामले में लापरवाही बरतने पर अखंडनगर थानाध्यक्ष संत कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है, जबकि क्षेत्राधिकारी कादीपुर के खिलाफ जांच एएसपी को सौंपी गई है।

यह अभियुक्त बने इनामिया

इनाम घोषित आरोपियों में अखंडनगर थाना क्षेत्र के रतनपुर (मैरवा) निवासी अरुण कुमार सिंह, कल्याणपुर के अमन यादव व आनंद यादव, चंदीपुर के सतीश, नमीत सिंह उर्फ अमित सिंह, अलीमुद्दीनपुर के विनय सिंह उर्फ पप्पू, विरसिंहपुर के आदर्श सिंह, मलीपुर के नेमपुर निवासी हलचल तिवारी, जौनपुर जिले के सरपतहा थाना क्षेत्र के नितिन तिवारी, मनीष उर्फ महेश तिवारी, बक्शा के महनपुर निवासी विशाल सिंह उर्फ बागी तथा आमवा गांव के दुर्गेश दूबे शामिल हैं।

कोल्ड स्टोरेज हादसा: पूर्व मंत्री समेत कई पर एफआईआर

- सोमवार को दूसरे पर फाफामऊ क्षेत्र में ढह गया था कोल्ड स्टोर का एक हिस्सा

एजेंसी । प्रयागराज

फाफामऊ क्षेत्र में हुए कोल्ड स्टोरेज हादसे के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए पूर्व मंत्री अंसार अहमद, स्टोरेज मैनेजर और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना को लेकर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद से कोल्ड स्टोरेज मालिक अंसार अहमद और मैनेजर का पता नहीं चल सका है। दोनों की तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं। अंसार अहमद का राजनीतिक सफर भी चर्चा में है। वह पूर्व में विधायक रह चुके हैं और बाद में राज्य सरकार में मंत्री पद भी संभाल चुके हैं। फिलहाल वे सक्रिय जनप्रतिनिधि नहीं हैं।

नीतीश फिर संभालेंगे जदयू की जिम्मेदारी

- चौथी बार बने निर्विरोध अध्यक्ष, 2028 तक बना रहेगा कार्यकाल

एजेंसी । पटना

बिहार के मुख्यमंत्री Nitish Kumar को एक बार फिर जनता दल (यूनाइटेड) का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिया गया है। उनका यह चौथा कार्यकाल होगा और वे वर्ष 2028 तक इस पद पर बने रहेंगे। पार्टी के चुनाव अधिकारी Anil Hegde दोपहर बाद उन्हें औपचारिक रूप से निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपेंगे। इस पद के लिए केवल नीतीश कुमार ने ही नामांकन किया था, जिसके चलते चुनाव प्रक्रिया महज औपचारिकता बनकर रह गई।

2016 में पहली बार बने थे अध्यक्ष

जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष Sanjay Jha के अनुसार, नीतीश कुमार ने 19 मार्च को नई दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में नामांकन दाखिल किया था। नामांकन वापसी की तय समयसीमा तक किसी अन्य दावेदार के सामने न आने से उनका निर्विरोध निर्वाचन सुनिश्चित हो गया। गौरतलब है कि नीतीश कुमार पहली बार 2016 में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। जब शरद यादव ने पद छोड़ा था। इसके बाद 2019 में भी उन्होंने यह जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 2020 में उन्होंने पद छोड़कर आरसीपी सिंह को जिम्मेदारी सौंपी थी। बाद में लल्लन सिंह ने अध्यक्ष पद संभाला, जिन्होंने दिसंबर 2023 में इस्तीफा दे दिया। लगातार संगठनात्मक फेरबदल के बाद नीतीश कुमार की वापसी के साथ पार्टी नेतृत्व एक बार फिर उनके हाथों में केंद्रित हो गया है।

सुकमा में बदली तस्वीर: 20 साल बाद खुले 123 स्कूलों के ताले

एजेंसी । सुकमा

नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। वर्ष 2006 में नक्सली प्रभाव और सलवा जुडूम के दौर में बंद हुए 123 स्कूल अब पूरी तरह फिर से संचालित हो रहे हैं। इनमें 102 प्राथमिक और 21 माध्यमिक विद्यालय शामिल थे। प्रशासन के अनुसार, लगातार प्रयासों और राज्य सरकार की योजनाओं के चलते जिले में अब ऐसा कोई स्कूल नहीं बचा है जो नक्सल दहशत के कारण बंद हो। दूरस्थ और संवेदनशील इलाकों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया गया है।

डबल मर्डर: MLC कमलेश पाठक को छह साल की सजा

- आठ अन्य आरोपियों को पांच-पांच वर्ष कारावास
- 15 मार्च 2020 में हुई थी अधिवक्ता की हत्या

एजेंसी । औरैया

बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड से जुड़े गैंगस्टर एक्ट मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व एमएलसी Kamlesh Pathak को छह वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा दी है। साथ ही आठ अन्य दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सजा और 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। एमपी-एमएलए कोर्ट (एफटीसी द्वितीय) ने साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध होने के बाद यह फैसला सुनाया।

संतोष पाठक समेत 11 नामजद

यह मामला 15 मार्च 2020 का है, जब औरैया शहर के पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में कमलेश पाठक, उनके भाई एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख संतोष पाठक समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि, मामले में नामजद गनर अवनीश प्रताप को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर अदालत ने बरी कर दिया। पुलिस जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

दोहरे हत्याकांड का मामला विचाराधीन

जिसके आधार पर आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित आरोपों में दोषियों को दंडित किया। अदालत के आदेश के अनुसार सभी दोषी फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में रहेंगे। वहीं, मूल दोहरे हत्याकांड से जुड़ा मामला अभी विचाराधीन है और उस पर अंतिम निर्णय आना बाकी है। 11 में एक आरोपी किशोर था, उसकी सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। गैंगस्टर मामले में फरवरी में ही लगभग सुनवाई पूरी हो चुकी थी।

व्यापार जगत

पश्चिम एशिया से राहत के संकेत, झूमा बाजार

- निवेशकों को 7.95 लाख करोड़ का लाभ
- शेयर बाजार में उछाल दिनभर हुई खरीदार

एजेंसी । नई दिल्ली

वैश्विक संकेतों और पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद ने घरेलू शेयर बाजार में जोरदार तेजी ला दी। कारोबार के अंत में BSE Sensex 1.89% और Nifty 50 1.78% की मजबूती के साथ बंद हुए, जिससे निवेशकों की संपत्ति में करीब 7.95 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। दिन की शुरुआत मजबूती के साथ हुई, हालांकि शुरुआती सत्र में उतार-चढ़ाव बना रहा।

बैंकिंग, आटो में जमकर खरीदारी

दोपहर बाद ईरान की ओर से क्षेत्रीय तनाव कम करने के संकेत मिलते ही बाजार में चौतरफा खरीदारी तेज हो गई, जिससे सूचकांकों ने ऊंची छलांग लगाई। बीच-बीच में मुनाफावसूली के बावजूद तेजी का रुख कायम रहा। सेक्टोरल स्तर पर बैंकिंग, ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में सबसे अधिक खरीदारी देखी गई और ये सूचकांक 2% से ज्यादा चढ़कर बंद हुए। आईटी, एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी, ऑयल एंड गैस और पीएसयू शेयरों में भी मजबूती रही।

मार्केट कैप 423.17 लाख करोड़

व्यापक बाजार में भी तेजी दिखी, जहां मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक 2.6% से अधिक उछले। बाजार पूंजीकरण के लिहाज से बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल मार्केट कैप 423.17 लाख करोड़ रुपये (अनंतिम) तक पहुंच गया, जो पिछले सत्र के 415.22 लाख करोड़ रुपये से उल्लेखनीय बढ़त दर्शाता है। कारोबार के दौरान बीएसई में 4,431 शेयरों में ट्रेडिंग हुई, जिनमें से करीब दो-तिहाई शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। एनएसई में भी अधिकांश शेयर हरे निशान में रहे। सेंसेक्स के 30 में से 28 और निफ्टी के 50 में से 44 शेयर लाभ के साथ बंद हुए।

1793 अंक उछला सेंसेक्स

इंडेक्स मूवमेंट की बात करें तो सेंसेक्स ने दिन में 1,793 अंकों तक की उछाल दर्ज की, जबकि निफ्टी 23,000 के ऊपर तक पहुंच गया था। अंत में हल्की मुनाफावसूली के चलते दोनों सूचकांक ऊपरी स्तर से थोड़ा नीचे बंद हुए। दिग्गज शेयरों में एटरनल, Asian Paints और Bajaj Finance प्रमुख बढ़त वाले शेयरों में शामिल रहे। वहीं Sun Pharmaceutical Industries और Cipla में गिरावट दर्ज की गई।

डीपीआईआईटी- ब्लू स्टार के बीच करार

- विनिर्माण स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा

एजेंसी । नई दिल्ली

देश में विनिर्माण क्षेत्र में नवाचार को गति देने के लिए Department for Promotion of Industry and Internal Trade (डीपीआईआईटी) ने Blue Star Limited के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य स्टार्टअप्स और उद्यमियों को उद्योग से जोड़ते हुए तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना है। समझौते पर डीपीआईआईटी के उप सचिव टी.एल.के. सिंह और ब्लू स्टार के प्रबंध निदेशक बी. थियागराजन ने हस्ताक्षर किए।

स्टार्टअप्स को उपलब्ध होगा बाजार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, इस पहल के तहत स्टार्टअप्स को विशेषज्ञ मार्गदर्शन, अनुसंधान एवं विकास (R&D) सुविधाएं, परीक्षण अवसंरचना और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट (PoC), उत्पाद सत्यापन और औद्योगिक मूल्य श्रृंखला में एकीकरण के लिए भी सहयोग दिया जाएगा। यह साझेदारी स्टार्टअप्स को वास्तविक उद्योग जरूरतों के अनुरूप समाधान विकसित करने में सक्षम बनाएगी।

नवाचार को बढ़ावा देने की तैयारी

इसके अलावा, दोनों संस्थाएं मिलकर 'स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज' और लक्षित हैकाथॉन जैसे कार्यक्रमों के आयोजन की संभावनाएं भी तलाशेंगी, जिनका फोकस एचवीएसी और विनिर्माण क्षेत्र पर रहेगा। डीपीआईआईटी के अधिकारियों के अनुसार, यह पहल उद्योग-आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्टार्टअप्स को बड़े पैमाने पर समाधान लागू करने के लिए मंच उपलब्ध कराएगी। यह सहयोग विशेष रूप से एचवीएसी तकनीक, डिजिटल समाधान, उन्नत विनिर्माण और सप्लाई चेन इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे उत्पाद-आधारित स्टार्टअप्स को समर्थन देने पर केंद्रित है।

पूर्व चेयरमैन के आरोपों की जांच कराएगी बैंक

एजेंसी । नई दिल्ली

HDFC Bank ने पूर्व अंशकालिक चेयरमैन अतानु चक्रबर्ती के इस्तीफे में उठाए गए मुद्दों की स्वतंत्र जांच कराने का फैसला किया है। इसके लिए बैंक ने बाहरी विधि फर्मों को नियुक्त किया है, ताकि पूरे मामले का निष्पक्ष और तथ्य आधारित आकलन किया जा सके। बैंक के प्रवक्ता के अनुसार, यह कदम पारदर्शिता और कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्च मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। बाहरी एजेंसियां इस्तीफे में उठाए गए सभी बिंदुओं की स्वतंत्र समीक्षा करेंगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

2027 तक बढ़ाया गया था कार्यकाल

चक्रवर्ती मई 2021 में अंशकालिक चेयरमैन नियुक्त किए गए थे और उनका कार्यकाल 2027 तक बढ़ाया गया था। वे 1985 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं और वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सहित कई अहम पदों पर कार्य कर चुके हैं।

तनाव में नरमी से ब्रेंट 103 डॉलर के करीब

- ब्रेंट क्रूड में 2.7 फीसद का उछाल, डब्ल्यूटीआई क्रूड में तेजी बरकरार

एजेंसी । नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में हालात नरम पड़ने के संकेतों के बावजूद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। Brent Crude करीब 103 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि WTI Crude में भी तेज़ी जारी है। मंगलवार के कारोबार में ब्रेंट क्रूड करीब 2.7 फीसदी उछलकर 102 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया, वहीं डब्ल्यूटीआई भी लगभग 3 फीसदी की बढ़त के साथ 90 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है।

स्ट्रेट आफ होर्मुज को लेकर निवेशक सतर्क

विश्लेषकों के मुताबिक, ईरान की ओर से बातचीत को लेकर अनिश्चित संकेत और भू-राजनीतिक जोखिमों के कारण बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। खासतौर पर Strait of Hormuz की स्थिति को लेकर निवेशक सतर्क हैं, क्योंकि इस मार्ग से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। हालांकि, इससे पहले अमेरिकी पक्ष की ओर से बातचीत में प्रगति के संकेत मिलने पर तेल कीमतों में तेज गिरावट भी देखी गई थी, लेकिन ताजा घटनाक्रम ने फिर से बाजार में अनिश्चितता बढ़ा दी है।

ब्रेंट की कीमत 85 डॉलर रहने का अनुमान

इस बीच, Goldman Sachs ने वर्ष 2026 के लिए अपने तेल मूल्य अनुमान को संशोधित करते हुए ब्रेंट की औसत कीमत 85 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई की 79 डॉलर प्रति बैरल रहने का अनुमान जताया है, जो पहले के अनुमान से अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक पश्चिम एशिया में स्थिति पूरी तरह स्थिर नहीं होती, तब तक कच्चे तेल के दामों में उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। वहीं डब्ल्यूटीआई भी लगभग 3 फीसदी की बढ़त के साथ 90 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है। मंगलवार के कारोबार में ब्रेंट क्रूड करीब 2.7 फीसदी उछलकर 102 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया।

वैश्विक चुनौतियों के बीच निर्यात 714 अरब डॉलर के पार

एजेंसी । नई दिल्ली

वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का निर्यात लगातार मजबूती दिखा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल से जनवरी के दौरान देश का कुल निर्यात बढ़कर 714.73 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 679.02 अरब डॉलर के मुकाबले यह 5.26 प्रतिशत की वृद्धि है, जो आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं, भू-राजनीतिक तनाव और कमोडिटी कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत की आर्थिक लचीलापन दर्शाती है। सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं,

जिनमें जोखिम कम करने हेतु 'रिलीफ' स्कीम भी शामिल है। मंत्री के अनुसार, निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने और वैश्विक बाजारों में हिस्सेदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दीर्घकालीन रुझान भी सकारात्मक रहे हैं। वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 के बीच निर्यात में करीब 6.9 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई, जिससे कुल निर्यात 497.90 अरब डॉलर से बढ़कर 828.25 अरब डॉलर तक पहुंच गया।

आईपीएल का काउंटडाउन

चौके-छक्के बरसाने को तैयार 'बाउंड्री के बादशाह'

एजेंसी । मुंबई

टी-20 क्रिकेट में बाउंड्री लगाने की रफ्तार तेज हो रही है और आईपीएल 2026 इसी बदलाव का अगला चरण साबित हो सकता है। आंकड़े बताते हैं कि कुछ बल्लेबाज ऐसे हैं जिनकी मारक क्षमता और खेल का तरीका इस सीजन की दिशा तय कर सकते हैं।

बाउंड्री की रफ्तार

आईपीएल 2024 में औसतन हर 5.03 गेंद पर एक बाउंड्री लग रही थी, जो 2025 में घटकर 4.67 गेंद पर आ गई है।- इसका सीधा मतलब है कि अब लगभग हर ओवर में 1 से ज्यादा बाउंड्री देखने को मिल रही है।- बाउंड्री जल्दी-जल्दी लगने से साफ है कि बल्लेबाज अब पहले से ज्यादा आक्रामक खेल रहे हैं।

किन गेंदों पर सबसे ज्यादा हमला?

आंकड़ों के मुताबिक बल्लेबाजों ने फुल लेंथ और स्लॉट में आई गेंदों पर सबसे ज्यादा बाउंड्री हासिल की हैं।- स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ मध्य के ओवरों में छक्कों की दर में स्पष्ट बढ़ोतरी देखी गई है।- पावरप्ले में तेज गेंदबाजों के खिलाफ चौकों की संख्या सबसे ज्यादा रही है।

अभिषेक शर्मा की संतुलित और आक्रामक बल्लेबाजी का जलवा

अभिषेक शर्मा जून 2025 के बाद टी-20 क्रिकेट में अपनी तेजतर्रार बल्लेबाजी के लिए खास पहचान बना चुके हैं। उन्होंने हर 2.99 गेंद में एक बाउंड्री लगाकर 100 बाउंड्री लगाने वाले बल्लेबाजों में सबसे तेज दर हासिल की है। उनकी खासियत यह है कि वे सिर्फ लेग साइड पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि ऑफ साइड पर भी उतनी ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं।

संजू सैमसन की ऑलराउंड बल्लेबाजी ने मचाया धमाल

संजू सैमसन हालिया टी-20 विश्व कप पारियों में शानदार फॉर्म में नजर आए हैं। उनकी बल्लेबाजी का खास पहलू ऑफ साइड पर उनका दबदबा रहा, जहां उन्होंने हर 2.59 गेंद में एक बाउंड्री लगाई—जो 100 रन बनाने वाले बल्लेबाजों में सबसे बेहतर प्रदर्शन है। इतना ही नहीं, ऑफ साइड पर 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले वे इकलौते बल्लेबाज भी रहे।

फिन एलेन का धमाकेदार प्रदर्शन

जून 2025 के बाद से फिन एलेन ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टी20 क्रिकेट में खास पहचान बनाई है। इस अवधि में उन्होंने 30 मैचों में 1177 रन बनाए, जिसमें उनका शानदार स्ट्राइक रेट 200.17 रहा। एलेन ने 9 अर्धशतक और 3 शतक जड़कर यह साबित किया कि वे सिर्फ तेजी से रन बनाने वाले बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि बड़ी पारियां खेलने में भी लगातार सफल हैं।

ईशान किशन की विस्फोटक बल्लेबाजी, हर दिशा में दबदबा

ईशान किशन जून 2025 के बाद टी-20 क्रिकेट में सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में उभरकर सामने आए हैं। इस दौरान 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ियों में उनका स्ट्राइक रेट 202.12 सबसे ज्यादा रहा। उनकी निरंतरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वे लगभग हर 3 गेंद में एक बाउंड्री लगाने में सफल रहे। खासतौर पर लेग साइड पर उनका दबदबा देखने को मिला, जहां से उनके 69.17% रन आए। इस क्षेत्र में उन्होंने 135 शॉट्स में 61 बाउंड्री लगाईं, यानी हर 2.27 गेंद में एक बाउंड्री।

वैभव सूर्यवंशी का तूफानी प्रदर्शन, टी-20 में छाए

वैभव सूर्यवंशी ने हालिया टी-20 पारियों में विस्फोटक बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा है। पिछली 10 पारियों में उन्होंने 436 रन 202.79 के शानदार स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। उनकी आक्रामकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वे हर 3.03 गेंद में एक बाउंड्री और हर 5.97 गेंद में एक छक्का लगा रहे हैं। 20 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों में उनकी सिक्स हिटिंग दर सबसे तेज खिलाड़ियों में शामिल है। खासतौर पर तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनका प्रदर्शन बेहद खतरनाक रहा है, जहां उन्होंने 221.12 के स्ट्राइक रेट से 71 गेंदों में 27 बाउंड्री (जिसमें 16 छक्के शामिल हैं) जड़कर अपनी जबरदस्त फॉर्म साबित की है।

शिमरन हेटमायर की विस्फोटक लय जारी

शिमरन हेटमायर जून 2025 के बाद से टी-20 क्रिकेट में शानदार लय में नजर आ रहे हैं। नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 12 पारियों में 40.80 की औसत और 180 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। आईपीएल 2025 के बाद सभी टी-20 मुकाबलों में उन्होंने कुल 105 छक्के जड़े हैं, जो इस दौरान दूसरे सबसे ज्यादा हैं। खास बात यह है कि 51 पारियों में उनका औसतन हर मैच में 2 छक्के लगाने का रिकॉर्ड उनकी लगातार आक्रामक बल्लेबाजी और सिक्स हिटिंग क्षमता को दर्शाता है।

पिछले तीन महीने कप्तानी का सबसे कठिन दौर : स्टोक्स

एजेंसी । लंदन

इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने पिछले तीन महीने को अपनी कप्तानी का सबसे कठिन दौर बताया है। हालांकि यह भी दोहराया कि वह टीम को फिर तैयार करने को प्रतिबद्ध हैं। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की कि एशेज सीरीज 1-4 से हारने के बावजूद स्टोक्स, मैकुलम और प्रबंध निदेशक रॉब की पद पर बने रहेंगे। स्टोक्स ने अपनी, की और मैकुलम की तस्वीर इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए भावुक पत्र में लिखा-इंग्लैंड का कप्तान बनना एक खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। यह आपको मुस्कुराने के मौके देता है तो रुलाता भी है। पिछले तीन महीने कप्तानी के मेरे सफर का सबसे कठिन दौर रहा। इसने कई तरह से मेरी परीक्षा ली और मुझे यकीन है कि हर कप्तान के जीवन में ऐसा दौर आता है। पर बाज, रॉब और मेरे भीतर टीम को आगे ले जाने की इच्छा और जुनून है। हम अपना सब कुछ झोंक देंगे।

राजस्थान 15 हजार करोड़ में बिकने को तैयार

एजेंसी । नई दिल्ली

आईपीएल का नया सत्र शुरू होने से चार दिन पूर्व ही पहले सत्र के विजेता राजस्थान रॉयल्स (आरआर) को नया मालिक मिल गया है। अमेरिका स्थित काल सोमानी के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम (समूह) को 1.63 अरब डॉलर (लगभग 15,290 करोड़ रुपये) में बेचे जाने की तैयारी है। यह लीग के इतिहास का सबसे बड़ा करार होगा। इस कंसोर्टियम में वॉलमार्ट परिवार से जुड़े रॉब वॉलटन और फोर्ड परिवार से जुड़े हैंप परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। एरिजोना स्थित टेक उद्यमी काल सोमानी ने इन्ट्राएज, 'टूयो डॉट एआई' और एकेडेमियन जैसी कंपनियों की स्थापना की है। इस मामले की जानकारी रखने वाले विश्वसनीय सूत्र ने कहा, सोमानी पहले से ही फ्रेंचाइजी में निवेशक हैं। इस सौदे पर बीसीसीआई की मंजूरी के बाद जल्द ही हस्ताक्षर किया जाएगा। 1.63 अरब डॉलर की कीमत दर्शाती है कि आईपीएल एक ब्रांड के रूप में कितना आगे बढ़ चुका है। मुझे उम्मीद है कि अगले चार से पांच दिनों में इस समझौते की घोषणा कर दी जाएगी।

इस सत्र के बाद होगा लागू

यह सौदा बीसीसीआई की मंजूरी के अधीन होगा और 2026 आईपीएल सत्र के बाद प्रभावी होगा। वर्तमान में ब्रिटिश-भारतीय कारोबारी मनोज बादले के पास टीम में 65 प्रतिशत हिस्सेदारी है। 2008 में जब राजस्थान को खरीदा गया था, तब इसकी कीमत सिर्फ 67 मिलियन डॉलर (260-270 करोड़ रुपये) थी। अगर उसी 67 मिलियन डॉलर को आज की वैल्यू में देखा जाए तो यह करीब 628 करोड़ बनता है। अब 2026 में यही फ्रेंचाइजी करीब 15 हजार करोड़ में बिकी है। यानी मौजूदा वैल्यू की तुलना 2008 की आज की कीमत (628 करोड़) से करें तो राजस्थान की कीमत में करीब 24 गुना का उछाल आया है।

दो साल का लगा था प्रतिबंध

शेन वॉर्न की कप्तानी में राजस्थान (2008) ने लीग का पहला खिताब जीता था। उसके बाद टीम 2022 में ट्रॉफी के करीब पहुंचीं पर जीत नहीं पाई। गुजरात टाइटंस से फाइनल में उसे हार मिली थी। फ्रेंचाइजी पर 2016 और 2017 में दो साल का प्रतिबंध भी लगा था।

श्रीलंका ने आईपीएल के लिए ईशान मलिंगा को मंजूरी दी

एजेंसी । कोलंबो

श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने ईशान मलिंगा को आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) की ओर से हिस्सा लेने की मंजूरी दे दी है, लेकिन बाकी तीन नुवान तुषारा, वानिंदु हसरंगा और मथीशा पथिराना के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है। टीम का पहला मुकाबला 28 मार्च को चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल के पहले मैच में होम टीम और मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स से होगा। टीम के कप्तान ईशान किशन बुधवार को मुंबई में कप्तानों की मीटिंग में शामिल होंगे।

टी-20 रैंकिंग में मंधाना दूसरे स्थान पर कायम

एजेंसी । दुबई

भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने आईसीसी महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरा स्थान बरकरार रखा है। दूसरी ओर, कप्तान हरमनप्रीत कौर मंगलवार को जारी नवीनतम रैंकिंग में 14वें स्थान पर पहुंच गईं। छठे स्थान पर कायम आक्रामक बल्लेबाज शेफाली वर्मा शीर्ष 10 में दूसरी भारतीय है। जेमिमा रोड्रिग्स संयुक्त 11वें स्थान पर बरकरार हैं।गेंदबाजी में स्पिन ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा एक पायदान चढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गईं जबकि तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर छठे स्थान पर बनी हुई हैं। दीप्ति ऑलराउंडरों की रैंकिंग में भी तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं।ऑस्ट्रेलिया की सलामी बल्लेबाज जॉर्जिया वोल पहली बार रैंकिंग के शीर्ष 10 में शामिल हुईं जबकि न्यूजीलैंड की स्टार सोफी डिवाइन के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार दो अर्धशतकों ने उन्हें दो पायदान ऊपर 18वें स्थान पर पहुंचा दिया। पदार्पण मैच में (घाना के खिलाफ) शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बनीं रवांडा की 15 वर्षीय फैनी उटागुशिमानिंदे ने 66वें स्थान पर रैंकिंग में प्रवेश किया है।

बॉलीवुड

'भूत बंगला' के नए गाने 'तू ही दिसदा' ने बढ़ाई उत्सुकता

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की आगामी फिल्म 'भूत बंगला' का दूसरा गाना 'तू ही दिसदा' रिलीज हो गया है, जिसे दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। 23 मार्च को जारी हुए टीजर के बाद से ही फैंस इस रोमांटिक ट्रैक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गाने में अक्षय कुमार और वामिका गब्बी की केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। इस खूबसूरत गाने को मशहूर गायक अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने अपनी आवाज दी है, जबकि इसका प्रीतम ने तैयार किया है। गाने के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी धुन और बोलों की जमकर तारीफ हो रही है। अक्षय कुमार ने भी अरिजीत सिंह का आभार जताते हुए कहा कि उनके साथ काम करना हमेशा खास अनुभव होता है। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी 'भूत बंगला' एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जो 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म में तब्बू, परेश रावल और राजपाल यादव जैसे अनुभवी कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

'सरकार 4' को लेकर राम गोपाल वर्मा का बड़ा फैसला

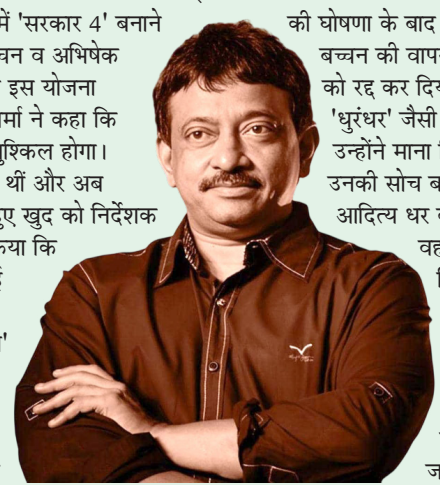

राम गोपाल वर्मा ने अपनी चर्चित फ्रैंचाइजी 'सरकार' की चौथी किस्त को लेकर बड़ा फैसला लिया है। हाल ही में 'सरकार 4' बनाने की घोषणा के बाद फैंस में उत्साह था और अमिताभ बच्चन व अभिषेक बच्चन की वापसी को लेकर चर्चाएं तेज थीं, लेकिन अब निर्देशक ने इस योजना को रद्द कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राम गोपाल वर्मा ने कहा कि 'धुरंधर' जैसी फिल्मों के बाद गैंगस्टर जॉनर में नई फिल्म चलाना मुश्किल होगा। उन्होंने माना कि उनकी पिछली फिल्में 'द गॉडफादर' से प्रेरित थीं और अब उनकी सोच बदल गई है। उन्होंने 'धुरंधर 2' की सराहना करते हुए खुद को निर्देशक आदित्य धर का प्रशंसक भी बताया। राम गोपाल वर्मा ने साफ किया कि वह अब 'सरकार 4' नहीं, बल्कि 'सिंडिकेट' नाम की नई फिल्म पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट उनके लिए बेहद ईमानदार प्रयास होगा और 'सत्या' के बाद उनका सबसे सच्चा काम साबित हो सकता है। निर्देशक के अनुसार, वह अपनी पूरी ऊर्जा इस नई फिल्म में लगाना चाहते हैं, हालांकि इसके परिणाम को लेकर उन्होंने अनिश्चितता भी जताई है।

'दृश्यम 3' की रिलीज डेट बदली, नई तारीख का ऐलान

मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की आगामी फिल्म 'दृश्यम 3' का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं। पहले इसकी रिलीज तारीख 2 अप्रैल चुनी गई थी, लेकिन कुछ वक्त से इसमें बदलाव की खबरें सामने आने लगी है। अब खुद सुपरस्टार ने इन खबरों की पुष्टि कर दी है। उन्होंने फिल्म का पोस्टर जारी करते हुए इसकी नई रिलीज तारीख से पर्दा उठाया है। दिलचस्प बात यह है कि 'दृश्यम 3' की रिलीज के लिए बेहद खास दिन को चुना गया है। 'दृश्यम 3' इस तारीख को सिनेमाघरों में देगी दस्तकमोहनलाल ने सोशल मीडिया पर 'दृश्यम 3' की नई रिलीज तारीख बताई है। पोस्ट के मुताबिक, फिल्म अब 21 मई को रिलीज होगी, जिस दिन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता का जन्मदिन भी है। सुपरस्टार ने पोस्ट जारी करते हुए कैप्शन दिया, 'अतीत कभी चुप नहीं रहता... वह सिर्फ इंतजार करता है। जॉर्जकुट्टी आ रही है, 21 मई, 2026 'दृश्यम 3' दुनिया भर में रिलीज।' फिल्म के नए पोस्टर में मोहनलाल 'जॉर्जकुट्टी' के किरदार में बेहद शांत दिखाई दे रहे हैं। 'दृश्यम 3' की रिलीज तारीख बदलने के पीछे का कारण नहीं बताया गया है। कुछ दिन पहले ट्रेड ट्रैकर श्रीधर पिल्लई ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि खाड़ी देशों में पैदा हुई स्थिति के कारण यह बदलाव किया जा सकता है। दरअसल, खाड़ी देशों में मलयालम सिनेमा का बड़ा बाजार है और निर्माता कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। इससे पहले, यश अभिनीत 'टॉक्सिक' की रिलीज तारीख जून, 2026 तक के लिए स्थगित की जा चुकी है।

मशहूर रैपर बादशाह ने चुपचाप की दूसरी शादी

मशहूर रैपर बादशाह इन दिनों अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को लेकर चर्चा में हैं। एक ओर उनका हालिया गाना 'टटीरी' कथित अश्लीलता के आरोपों के चलते विवादों में घिरा हुआ है, वहीं दूसरी ओर उनकी शादी की खबरों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बादशाह ने अभिनेत्री और मॉडल ईशा रिखी के साथ गुपचुप शादी रचा ली है। दरअसल, 24 मार्च को ईशा रिखी की मां पूनम रिखी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए, जिनमें बादशाह और ईशा शादी के पारंपरिक जोड़े में नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में दोनों को करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में वरमाला पहनते और पंडित के निर्देशानुसार शादी की रस्में निभाते देखा जा सकता है। हालांकि, इस पूरे मामले पर अब तक बादशाह या ईशा रिखी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। गौरतलब है कि बादशाह और ईशा रिखी के बीच डेटिंग की खबरें लंबे समय से सामने आती रही हैं। बताया जाता है कि दोनों की पहली मुलाकात एक कॉमन दोस्त की पार्टी में हुई थी और इसके बाद कई मौकों पर उन्हें साथ देखा गया। पिछले साल करण औजला के एल्बम लॉन्च इवेंट में भी दोनों की मौजूदगी ने इन अफवाहों को हवा दी थी। बता दें कि बादशाह की पहली शादी जैस्मीन मसीह से हुई थी, जिनसे उनका 2020 में तलाक हो गया था और उनकी एक बेटी भी है।

बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' का जलवा जारी

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। रिलीज के बाद से ही फिल्म ने कमाई के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और अब महज पांच दिनों में 500 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होकर इतिहास रच दिया है। दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया के चलते फिल्म निर्माताओं के लिए यह किसी 'नोट छापने की मशीन' से कम साबित नहीं हो रही है। ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म ने पांचवें दिन यानी सोमवार को 65 करोड़ रुपये का कारोबार किया। हालांकि वीकेंड के मुकाबले कमाई में गिरावट देखी गई, लेकिन इसके बावजूद फिल्म की रफ्तार मजबूत बनी हुई है। इससे पहले तीसरे दिन फिल्म ने 113 करोड़ और चौथे दिन 114.85 करोड़ रुपये कमाए थे। पांच दिनों में फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन 519.12 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि वर्ल्डवाइड स्तर पर इसने 829.76 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। वहीं, पवन कल्याण की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' को बॉक्स ऑफिस पर झटका लगा है। पहले दिन 34.75 करोड़ की ओपनिंग लेने के बाद फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। पांचवें दिन फिल्म ने केवल 1.96 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल कलेक्शन 62.26 करोड़ रुपये तक पहुंच सका है। फिल्म में राशि खन्ना और श्रीलीला भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रही हैं।

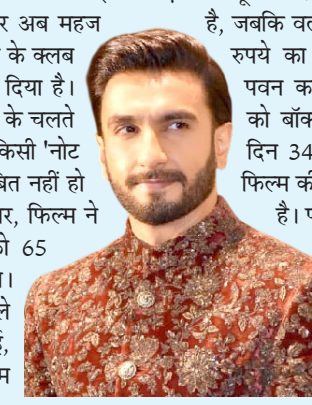

जीने की जंग के बाद अब सम्मानजनक मृत्यु

एजेंसी । गाजियाबाद

गाजियाबाद के हरीश राणा का आज दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। वे बीते 13 साल से कोमा में थे। देश के सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों उन्हें इच्छामृत्यु की इजाजत दी थी। हरीश राणा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल (आईआरसीएच) में भर्ती थे। उन्हें उपशामक देखभाल वार्ड में रखा गया था। अस्पताल में एक हफ्ते से उनकी गहन निगरानी जारी थी। 23 मार्च को डॉक्टरों ने बताया था। उन्हें कुछ दिन और निगरानी में रखा जा सकता है। वे पिछले एक सप्ताह से बिना खाना और पानी के जीवित थे। यह प्रक्रिया छह दिनों से चल रही थी। इस दौरान उनके माता-पिता किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे थे।

बेटे के निधन से पहले मां की प्रार्थना

हरीश की मां अस्पताल के गलियारे में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थीं। बेटे के निधन से पहले मां ने भावुक होकर अपनी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा सांस ले रहा है। उसकी धड़कन अभी भी चल रही है। मां ने यह भी कहा कि वह मुझे छोड़कर जा रहा है।

इच्छामृत्यु की प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इच्छामृत्यु की इजाजत मिलने के बाद यह प्रक्रिया शुरू हुई थी। हरीश राणा 13 साल से कोमा में थे। डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर रख रही थी। एक सप्ताह तक बिना भोजन और पानी के रहने के बाद उनका निधन हुआ। यह एक जटिल और संवेदनशील मामला था।

- हरीश राणा का निधन, 13 साल से थे कोमा में
- इच्छामृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली थी इजाजत

यह है मामला

जुलाई 2010 में हरीश ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था। वर्ष 2013 में वह अंतिम वर्ष के छात्र थे। इसी दौरान अगस्त 2013 में रक्षाबंधन वाले दिन बहन से मोबाइल फोन पर बात करते हुए पीजी की चौथी मंजिल से गिर गए थे। गंभीर रूप से घायल हरीश को तुरंत पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया। बाद में दिसंबर 2013 में उसे दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वह क्वाड्रिप्लेजिया से ग्रसित है। इस स्थिति में उसके हाथ-पैर पूरी तरह निष्क्रिय हो गए और वह जीवन भर बिस्तर पर रहने को मजबूर हो गए। हरीश के असहनीय दर्द और शारीरिक अक्षमता के कारण माता-पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट में इच्छामृत्यु की अपील की, जिसे 8 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। करीब आठ महीने बाद 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हरीश को इच्छामृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) की अनुमति दे दी।

सुप्रीम कोर्ट में पावर की जंग

एजेंसी । नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य पुलिस पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई में बाधा डालने के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा कानूनी टकराव देखने को मिला। शीर्ष अदालत ने इस मामले में मंगलवार को सुनवाई की, जिसमें केंद्र और राज्य के अधिकारों, जांच एजेंसियों की भूमिका और संघीय ढांचे जैसे गंभीर मुद्दों पर बहस हुई। अदालत ने फिलहाल सुनवाई खत्म करते हुए मामले को अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है। इस मामले में ईडी ने आरोप लगाया है कि जब वह तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक सलाहकार संगठन आई-पैक के दफ्तर में तलाशी कर रही थी, तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य पुलिस ने कार्रवाई में बाधा डाली। इसी को लेकर ED ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। मामले की सुनवाई जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने की।

क्या है पूरा विवाद और ईडी का आरोप क्या है?

ईडी का कहना है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच के तहत आई-पैक के दफ्तर में सर्च ऑपरेशन कर रही थी। इसी दौरान राज्य सरकार और पुलिस ने उनके काम में दखल दिया और जांच प्रक्रिया को प्रभावित किया। ईडी ने इसे कानून के राज पर हमला बताया और मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की।

- ईडी के अफसरों पर लगे गंभीर आरोप, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछे तीखे सवाल
- ममता बनर्जी पर भी ईडी की कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप

अप्रैल तक टली सुनवाई

राज्य सरकार ने क्या दलील दी?

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ वकीलों ने कहा कि ईडी की याचिका कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है। उनका तर्क था कि कोई केंद्रीय एजेंसी सीधे राज्य सरकार के खिलाफ इस तरह की याचिका नहीं दायर कर सकती। उन्होंने कहा कि ऐसा करना देश के संघीय ढांचे के लिए खतरनाक होगा और इससे राज्यों के अधिकार कमजोर होंगे।

क्या सुप्रीम कोर्ट में अधिकारों को लेकर सवाल उठे?

सुनवाई के दौरान सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि क्या ईडी या उसके अधिकारी अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। राज्य पक्ष ने कहा कि ईडी कोई व्यक्ति या नागरिक नहीं है, इसलिए उसे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का दावा करने का अधिकार नहीं है। वहीं, अदालत ने यह भी पूछा कि क्या ईडी के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से अपने अधिकारों के आधार पर याचिका दायर कर सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि अगर छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री दखल दें।

क्या मौलिक अधिकार का मुद्दा बना?

राज्य सरकार के वकीलों ने कहा कि ईडी का काम संवैधानिक नहीं बल्कि वैधानिक है, इसलिए उसके पास मौलिक अधिकारों का दावा करने का आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी अधिकारी को काम में बाधा आती है, तो उसके लिए अलग कानूनी प्रक्रिया है, न कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करना।

ईडी और केंद्र सरकार की क्या दलील रही?

केंद्र की ओर से कहा गया कि यह मामला बेहद गंभीर है और इसमें कानून के शासन का सवाल जुड़ा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अदालत को इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनका कहना था कि अगर जांच एजेंसियों को काम करने से रोका जाएगा।

क्या चुनावी समय को लेकर भी उठे सवाल?

सुनवाई के दौरान यह भी मुद्दा उठा कि मामला चुनाव से ठीक पहले क्यों लाया गया। अदालत ने साफ किया कि वह चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करना चाहती, लेकिन अगर कोई गंभीर आरोप है तो उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता।

क्या राज्य और केंद्र के टकराव का मामला बना?

यह मामला सिर्फ एक जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि केंद्र और राज्य के अधिकारों के टकराव का उदाहरण बन गया। राज्य सरकार ने कहा कि यदि केंद्रीय एजेंसियों को इस तरह की छूट दी गई, तो यह राज्यों की स्वायत्तता पर असर डालेगा।

अदालत ने फिलहाल क्या फैसला दिया?

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई पूरी करते हुए कहा कि मामले की आगे की सुनवाई अप्रैल में होगी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं दिया। अब इस केस में आगे की सुनवाई में यह तय होगा कि ईडी की याचिका स्वीकार होगी या नहीं।

एआईएडीएमके का घोषणा पत्र जारी

घोषणा पत्र में 297 वादों की झड़ी

एजेंसी । चेन्नई

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने अपना घोषणापत्र जारी कर बड़ा चुनावी दांव खेला है। पार्टी ने आम जनता, खासकर महिलाओं और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई बड़े वादे किए हैं। मुफ्त फ्रिज, नकद सहायता और राशन में अतिरिक्त सुविधाओं जैसे ऐलानों के जरिए सीधे मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। महासचिव एडप्पडी पलानीस्वामी ने बताया कि घोषणापत्र समाज के सभी वर्गों से सुझाव लेकर तैयार किया गया है, जिसमें महंगाई और बेरोजगारी से राहत पर जोर दिया गया है।

आर्थिक राहत और सामाजिक सुरक्षा पर जोर

घोषणापत्र में हर परिवार को 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता, महिलाओं को हर महीने 2 हजार रुपये, साल में तीन मुफ्त गैस सिलिंडर और राशन के साथ दाल व खाद्य तेल देने जैसे वादे शामिल हैं। इसके अलावा महिला मुखिया को मुफ्त फ्रिज, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाकर 2 हजार रुपये करने और बेघर परिवारों को पक्का घर देने का भी आश्वासन दिया गया है। इन घोषणाओं के जरिए पार्टी ने गरीब और जरूरतमंद वर्ग को सीधी राहत देने का प्रयास किया है।

युवाओं, रोजगार और अन्य बड़े ऐलान

युवाओं के लिए नए कारोबार शुरू करने हेतु 25 लाख रुपये तक ऋण देने, बेरोजगार स्नातकों को 2 हजार रुपये मासिक भत्ता देने और रोजगार में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए कानून लाने की बात कही गई है। कामकाजी महिलाओं को रियायती दर पर दोपहिया वाहन, ग्रामीण रोजगार योजना को 150 दिन तक बढ़ाने और शराब की दुकानों को धीरे-धीरे बंद करने जैसे फैसले भी शामिल हैं।

वॉर ब्रीफ

स्वास्थ्य सेवाओं और जन औषधि केंद्रों पर सरकार का जोर

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि देश में एंटी-रेबीज वैक्सीन और इम्युनोग्लोब्युलिन की कोई कमी नहीं है और इसकी आपूर्ति पर्याप्त है। उन्होंने बताया कि हर साल लाखों पशु-काटने के मामले सामने आते हैं, जिनके लिए टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। वहीं, देशभर में 18,646 जन औषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं, जहां लोगों को सस्ती दरों पर दवाएं मिल रही हैं, जिनकी संख्या पिछले वर्षों में तेजी से बढ़ी है।

केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नहीं बनेगा अलग मंत्रालय

नई दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और सीमावर्ती इलाकों के विकास को लेकर सरकार ने लोकसभा में अपनी स्थिति साफ कर दी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि फिलहाल केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग मंत्रालय या नई नीति बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वहीं, सीमा से सटे क्षेत्रों में विकास के लिए चल रही योजनाओं के जरिए बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। सरकार का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था के तहत ही योजनाओं का प्रभावी संचालन और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम जारी है। नित्यानंद राय ने आगे बताया कि देश के केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 239 से 241 के तहत किया जाता है। उन्होंने कहा कि अभी सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग मंत्रालय, विशेष समिति या नई नीति बनाई जाए। उन्होंने बताया कि फिलहाल विभिन्न मंत्रालयों के बीच नियमित बातचीत और समन्वय से ही योजनाएं बनाई और लागू की जाती हैं। साथ ही, संसद की गृह मामलों की स्थायी समिति केंद्र शासित प्रदेशों के कामकाज की निगरानी और समीक्षा करती है।

सीमावर्ती इलाकों में विकास की नई रणनीति

- पुरानी बीएडीपी योजना आखिरी चरण में
- बुनियादी ढांचे के साथ अब रोजगार पर भी फोकस
- गांवों को विकसित कर मुख्यधारा से जोड़ने का लक्ष्य

एजेंसी । नई दिल्ली

देश के सीमावर्ती इलाकों के विकास को लेकर सरकार ने बड़ा खुलासा किया है। लोकसभा में बताया गया कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के तहत वित्त वर्ष 2004-05 से अब तक 39 हजार से ज्यादा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। सरकार ने यह भी साफ किया कि यह योजना अब अपने अंतिम चरण यानी 'सनसेट फेज' में पहुंच चुकी है। इसका उद्देश्य सीमा पर रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना रहा है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जवाब में बताया कि इन परियोजनाओं के तहत सड़क, पुल, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, आंगनवाड़ी और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। यह कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय सीमा से 0 से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों और कस्बों में लागू किया गया है।

क्या है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम?

सरकार के अनुसार बीएडीपी का मकसद सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करना है। इसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल, कृषि और छोटे उद्योग जैसे क्षेत्रों में काम किया गया। योजना का लक्ष्य इन क्षेत्रों को मुख्यधारा के विकास से जोड़ना और वहां रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं देना रहा है।

किस तरह के काम किए गए हैं?

मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत सड़कें, पुल और पुलिया बनाई गईं। इसके अलावा डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए आवास, अस्पतालों में अतिरिक्त कमरे, स्कूलों में क्लासरूम, आंगनवाड़ी केंद्र, छात्रावास और आजीविका से जुड़े प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए। इससे सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है।

वित्तीय स्थिति और हाल के खर्च का क्या आंकड़ा है?

सरकार ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में इस योजना के तहत 168.90 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह राशि पहले से स्वीकृत परियोजनाओं की देनदारियों को पूरा करने के लिए दी गई। इससे साफ है कि अब योजना अपने अंतिम चरण में है और नई परियोजनाओं की बजाय पुराने काम पूरे किए जा रहे हैं।

कांग्रेस ने ट्रांसजेंडर विधेयक का किया विरोध

- यह सांविधानिक अधिकारों पर सीधा हमला : राहुल गांधी

एजेंसी । नई दिल्ली

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार की ओर से लाया गया ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक सांविधानिक अधिकारों और ट्रांसजेंडर लोगों की पहचान पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस विधेयक का पूरी तरह विरोध करती है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि प्रस्तावित कानून ट्रांसजेंडर लोगों के मूल अधिकारों को कमजोर करता है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार का ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक ट्रांसजेंडर लोगों के सांविधानिक अधिकारों और

पहचान पर खुला हमला है। उन्होंने लिखा कि यह विधेयक ट्रांसजेंडर लोगों की खुद की पहचान का अधिकार छीन लेता है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है।

संसद में किसने पेश किया विधेयक?

संसद में यह विधेयक हाल ही में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने पेश किया है। विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि यह विधेयक ट्रांसजेंडर पहचान की परिभाषा को सीमित करता है और कानूनी मान्यता के लिए अतिरिक्त प्रक्रियाएं जोड़ता है।

मोस्ट वांटेड माओवादी सुकरु और चार अन्य ने किया आत्मसमर्पण

एजेंसी । भुवनेश्वर

ओडिशा में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। मोस्ट वांटेड माओवादी नेता सुकरु ने मंगलवार को कंधमाल जिले में आत्मसमर्पण कर दिया। उसके साथ चार अन्य माओवादियों ने भी हथियार डाल दिए। ओडिशा पुलिस के एंटी-नक्सल एडीजी संजीब पांडा ने आधिकारिक रूप से सरेंडर की पुष्टि करते हुए बताया कि सुकुरु लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर था। कंधमाल सहित आसपास के इलाकों में माओवादी गतिविधियों का सक्रिय सदस्य रहा है। पुलिस के अनुसार, सुकुरु पर 55 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। वह कई नक्सली वारदातों में शामिल रहा है और संगठन में उसका ऊंचा दर्जा माना जाता था। उसके आत्मसमर्पण को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में एसआईआर सुचारू रहा : सुको

एजेंसी । नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास अधिकांश राज्यों में सुचारू रूप से हुआ है, सिवाय पश्चिम बंगाल के। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत ने कहा कि अन्य राज्यों में एसआईआर अभ्यास के दौरान लगभग कोई मुकदमेबाजी नहीं हुई। सीजेआई ने कहा, पश्चिम बंगाल को छोड़कर जिन भी राज्यों में एसआईआर किया गया, हर जगह यह प्रक्रिया सुचारू (बिना बाधा के) रूप से चली। अन्य राज्यों में राज्यों में भी जटिलताएं हैं, लेकिन समान रूप से नहीं। लेकिन जटिलताएं तो हैं। लेकिन कुल मिलाकर अन्य राज्यों से शायद ही कोई मुकदमा आया। शीर्ष कोर्ट की ओर से ये टिप्पणियां उस समय आईं।

टीएमसी नेता के अनुरोध पर कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील और तृणमूल कांग्रेस की नेता मेनका गुरुस्वामी ने कोर्ट से अनुरोध किया कि पश्चिम बंगाल चुनाव में मतदाता सूची पर रोक की तारीख बढ़ाई जाए (ताकि सूची से अपना नाम हटा जाने पर आपत्ति जताने वाले व्यक्तियों के नामों पर फैसला किया जा सके और उन्हें मतदाता सूची में जोड़ा जा सके)। इसके जवाब में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस पर जरूर विचार करेगा।

पश्चिम एशिया में तनाव : लारिजानी की मौत के बाद नई नियुक्ति

मोहम्मद बाघेर जोलगाद्र बने ईरान का नए सुरक्षा प्रमुख

एजेंसी । तेहरान

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान ने अपने सुरक्षा ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। इस्राइल के हवाई हमले में शीर्ष नेता की मौत के बाद अब देश ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए सचिव की नियुक्ति कर दी है। क्षेत्र में हालात बेहद संवेदनशील होने के बावजूद यह फैसला लिया गया है। ईरान ने मंगलवार को पूर्व रिवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर मोहम्मद बाघेर जोलगाद्र को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सचिव नियुक्त किया। उन्होंने अली लारिजानी की जगह ली है, जिनकी पिछले सप्ताह इस्राइल

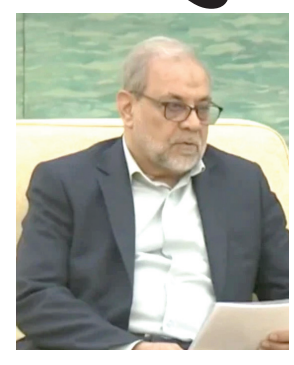

के एयरस्ट्राइक में मौत हो गई थी। सरकारी टीवी के मुताबिक, जोलगाद्र ब्रिगेडियर जनरल रैंक तक पहुंच चुके हैं और इससे पहले एक्सपीडिएंसी काउंसिल में भी अहम पद संभाल चुके हैं।

कौन हैं मोहम्मद बाघेर जोलगाद्र?

जोलगाद्र का जन्म 1954 में शिराज के फासा शहर में हुआ था। उन्होंने तेहरान विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पढ़ाई की। वे 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले भी सक्रिय रहे और बाद में रिवोल्यूशनरी गार्ड के अहम सदस्य बने। उनका परिवार भी कूटनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में प्रभावशाली माना जाता है। उनके दामाद काजेम गरीबाबादी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

क्या रहा है उनका विवादित और सैन्य इतिहास?

जोलगाद्र का नाम लंबे समय से ईरान की सैन्य और सुरक्षा संरचना से जुड़ा रहा है। वे रिवोल्यूशनरी गार्ड की इंटेलिजेंस यूनिट से भी जुड़े रहे हैं। उन पर अतीत में हमलों और सैन्य गतिविधियों में भूमिका के आरोप भी लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव के तहत उनका नाम प्रतिबंध सूची में भी शामिल रहा है, जो उनके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े होने के कारण जोड़ा गया।

क्या यह नियुक्ति ईरान की सख्त रणनीति का संकेत है?

जोलगाद्र की नियुक्ति को ईरान के भीतर बढ़ती सैन्य पकड़ के तौर पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फैसला बताता है कि ईरान अब ज्यादा सख्त और सुरक्षा-केंद्रित नीति अपनाने की दिशा में बढ़ रहा है। खासकर इस्राइल और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच यह नियुक्ति एक रणनीतिक संदेश भी मानी जा रही है।

क्या इससे क्षेत्रीय हालात और बिगड़ सकते हैं?

इस नियुक्ति का असर केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। पश्चिम एशिया में पहले से ही तनाव चरम पर है। ऐसे में एक सख्त छवि वाले सैन्य नेता का शीर्ष सुरक्षा पद पर आना आने वाले दिनों में हालात को और जटिल बना सकता है। इससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर भी असर पड़ने की संभावना है।